www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 09 | गोरखपुर, 25 अगस्त 2024 रविवार | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2

दरिन्दगी की हदें पार कर चुकी आदमी की पाशविक मानसिकता

शर्म की बात है कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ न छोटी बच्ची सुरक्षित है, न स्कूल-कॉलेज जाती लड़कियाँ और न घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग... महिलाओं पर यौन दुराचार के मामले पहले भी बढ़ रहे थे। और आगे भी बढ़ेंगे... कारण हमारी ऐसे मामलों को हैंडल करने की अप्रोच है, ढीला रवैया है और घृणित मानसिकता है। 2012 के नई दिल्ली के 'अमानवीय निर्भया कांड के बाद भी 3.33 लाख बलात्कार किए गए हैं. जबकि 1971-2022 के लंबे कालखंड में 8.23 लाख बलात्कार के केस दर्ज किए गए थे। बलात्कार किस गति और अनुपात से बढ़ रहे हैं, आश्चर्य होता है। क्या देश में बेटियां, बहनें और महिलाएं सिर्फ बलात्कार की 'वस्तु' बनकर रह गई हैं? क्या अब वे 'देवी' नहीं रहीं?

रेप की इन घटनाओं ने देश के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सभ्य कहलाए जाने वाले समाज में यह सब क्यों हो रहा है, क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। क्यों किसी को पुलिस और कानून का खौफ नहीं रह गया है। ऐसी घणित वारदातों के बाद देश की लगातार बिगड़ती छवि के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रहेंगी। सरकारों का काम क्या सिर्फ कानून बनाने तक सीमित रह गया है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने ऐसे हालात, परिवेश, अपराधों पर चिंता जताई है। उससे क्या होगा ? कल ही 32 लंबे सालों के बाद औरतों को इंसाफ मिला है आधा अधूरा 1992 में 100 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। विशेष अदालत ने सिर्फ 6 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। मौजूदा संदर्भों में क्या न्याय मिलेगा, देखते हैं। इस मुद्दे पर हो रही घिनौनी राजनीति भी बंद होनी चाहिए। यह मसला बहनों और बेटियों को अस्मिता से जुड़ा है। सारे समाज को मिलकर इस बुराई और बुरी प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ा होना होगा। कोलकाता की घटना के बाद से प्रशिक्षु डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। सरकार को रात की पाली में काम करने वाले डॉक्टरों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि चिकित्सा वर्ग की सुरक्षा व संरक्षा की मांग तार्किक है, जिसे नजर अंदाज नहीं ही किया जाना चाहिए। रात-दिन मुश्किल हालात में अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले डॉक्टरों को जिन संकटों से गुजरना पड़ता है, उसको लेकर चिंता होना वाजिव ही है। उचित होता यदि रोगियों की देखभाल की अनदेखी किये बिना संतुलित तरीके से समस्या का समाधान निकाला जाता। काले बैज पहनकर क्रमिक हड़ताल करना इसका एक प्रभावी विकल्प हो सकता था।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस को खूब फटकार लगाई है और उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। बेशक संदर्भ कोलकाता अस्पताल में एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार और बाद में हत्या का है, लेकिन शोषं अदालत का सरोकार राष्ट्रीय है। विशेषकर अस्पतालों में महिला डॉक्टर और नर्स आदि कैसे सुरक्षित रहे, इसके मद्देनजर एक टास्क फोर्स बनाने और अस्पतालों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने के महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी देशवासियों की आत्मा में लगातार गूंजती रहनी चाहिए कि बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म और हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। टास्क फोर्स को अपनी अंतरिम रपट तीन सप्ताह में देनी है और अंतिम रपट दो माह की अवधि में देनी है। फोर्स महिला सुरक्षा के उपाय सुझाएगी।

गौरतलब यह है कि 'निर्भया कांड' के एक साल बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा को अध्यक्षता में सख्त 'पॉक्सो एक्ट' बनाया गया। उसके बाद 'पॉश' (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमन एट वर्कप्लेस) एक्ट बनाया गया। फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया। क्या इन कानूनों ने बलात्कारियों को डराया ? हमारी व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। करीब 2.43 लाख केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इनमें पोक्सो केस भी हैं।

हर रोज बलात्कार के केस आ रहे हैं और सरकारें फास्ट ट्रैक कोर्ट के आश्वासन देती रहती है। पीड़िता को इंसाफ मिलना बहुत दूर की कौड़ी है। बहरहाल अब मौजूदा संदर्भ में सर्वोच्च अदालत के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा है, लेकिन आदमी की 'पाशविक 'हवस' अब दरिंदगी की हदें भी पार कर चुकी है। हम बलात्कारियों, हत्यारों को इंसान नहीं मान सकते, वे 'जानवर' से भी अधिक खौफनाक हैं अब हालात ये बन गए हैं कि बेशक बेटी 3-4 साल की हो और स्कूल जाना शुरू ही किया हो। बेटी बड़ी होकर कॉलेज में पढ़ती हो अथवा गहन पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हो और एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो। बेटी कहीं जाने के लिए राज्य परिवहन की बस में बैठी हो या बाजार में किसी काम से गई हो। उम्र 60 पार कर चुकी हो और विधवा महिला हो ! अब ऐसी बेटियों, नाबालिग या बालिग लड़कियां अथवा उम्रदराज विधवा महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वे सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। आखिर यह देश कैसा बन गया है? कोई भी राज्य इन जघन्य, वर्बर अपराधों से अछूता नहीं है। अभी तो सर्वोच्च अदालत के सामने वे ही तथ्य और आंकड़े आएंगे, जो पुलिस ने दर्ज किए होंगे। जिन्हें डर, खौफ के कारण दर्ज नहीं कराया गया अथवा पुलिस ने टालमटोल कर अपराध पर मिट्टी डाल दी, उन अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? 9 अगस्त 2024 को बंगाल से लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला उठा था और उसके बाद सोशल मीडिया पर हर जगह उनके लिए इंसाफ की गुहार लगी। घटना ने इंसानियत को ऐसे झकझोरा कि हर किसी को 2012 में निर्भया के साथ हुई वीभत्सता को याद आ गई। तुलना करते हुए कहा जाने लगा कि इतने साल बीत गए लेकिन समाज के हालात बिलकुल नहीं बदले हैं। आज भी जब बलात्कार का मुद्दा हर जगह गरमाया हुआ है। उस समय भी किसी किसी जगह कहीं महिला को कोई हैवान अपना निशाना रहा है। न छोटी बच्ची को छोड़ा जा रहा है नहीं बुजुर्ग महिला है को मौका मिलते ही लड़कियों को दबोचा जा रहा है और फिर वहशियत की हर हद पार हो रही है। बहुत पीछे न जाएँ और ये सोचें कि 9 अगस्त की घटना के बाद तो जैसे विरोध हो रहा है उससे इन घटनाओं में कमी आई होगी तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है। हर रोज दरिंदगी की नई सीमा तय होती है। बदलापुर से आज एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चार साल की दो बच्चियों का यौन शोषण उनके ही स्कूल के सफाईकर्मी ने किया। बच्चियाँ उस सफाईकर्मी को 'दादा' कहती थीं, उन्हें अपना परिचित समझती थीं, लेकिन उस जानने वाले ने उनके साथ क्या किया। मौका मिलते ही कपड़े उतारकर उनके निजी अंग को छूने का काम किया, उनका शोषण किया। इस घटना से कुछ दिन पहले 16 अगस्त 2024 राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में एक 63 वर्षीय महिला का घर में घुसकर सामूहिक रेप किया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि आरोपित घर में घुसे तो लूटपाट के लिहाज से थे लेकिन महिला को देख उन्होंने उसके साथ बारी-बारी रेप कर लिया।

सामाजिक संरचना पर सवाल खड़े करती बच्चों में हिंसक मानसिकता

बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है।

तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिमेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिमेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है।

यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं पातक रूप है।

बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है ! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं।

'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वच्छन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में मटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दुःख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बीना बना देता है। यह दकियानुसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मवादा, शिष्टाचार संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय

बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और जिले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं।शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगे, टोकेंगे नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी।एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है. वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगे, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं। स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए, खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पवजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरिज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है।

बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौड़ना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते है कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता।

वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन-कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे ! तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध के रूप में बाहर निकलता है।

फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू बातावरण न मिलना, माता-पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है। और वे हिंसक हो सकते हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षकों को बच्चों के आचरण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। ऐसा करने पर वे बच्चों के चाल- चलन की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा ?

▶ सीएम ने कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर साधा निशाना,

कांग्रेस पर जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धारा 370 और 35 (ए) हटाकर लाई गई शांति को कांग्रेस अपने गठबंधन से खतरे में डाल रही है, जिससे राजस्थान के लोगों में नाराजगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर जम्मू-कश्मीर में अशांति और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जिस जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए राजस्थान के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उसी राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी की राजनीति लोगों के मन में गहरी नाराजगी पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ₹प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 (ए) को हटाकर वहां अमन, समृद्धि और सुरक्षा की एक नई इबारत लिखी है। कांग्रेस पार्टी अब पाक प्रायोजित और परिवारवादी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर देश के मणि मुकुट को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रही है। शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर

वहां के युवाओं को गुमराह कर रही है, जिन्हें पहले ही परिवारवादी पार्टियों ने हाथ में एके-47 थमा दी थी। उन्होंने कहा, ₹कांग्रेस का इस तरह का समर्थन उसके देश विरोधी मंसूबों को बेनकाब करता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान के लोगों के मन में इस गठबंधन के खिलाफ गहरी नाराजगी है, और यह भावना उन बलिदानों को ध्यान में रखते हुए है जो राजस्थान के युवाओं ने जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए दिए थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह एक तरफ तो दलितों के अधिकारों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है।

इस अवसर पर मंच पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री के वक्तव्यों का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि भाजपा कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर अपनी आक्रामक रणनीति पर कायम है, और आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।

मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान में हाई अलर्ट

जयपुर। शियाई और अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के फैलने के कारण केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से आने वाले नागरिकों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विश्व में मंकी पॉक्स के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसके बाद राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने भी राज्य में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि, भारत में अभी तक इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसके कुछ मामले रिपोर्ट किए गए हैं।

राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस अस्पताल) के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि मंकी पॉक्स एक वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जिसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है। इस बीमारी के लक्षण हर्पीज और चिकन पॉक्स से मिलते-जुलते हैं और इसे एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।

मंकी पॉक्स के लक्षण

मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर मटर के दाने जितने बड़े दर्दनाक दाने निकल आते हैं। इसके साथ ही तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ मामलों में इस बीमारी से मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। संक्रमित होने के लगभग तीन सप्ताह बाद इस बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं।

कैसे फैलता है और इससे बचाव के उपाय

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा, जानवरों का शिकार करते समय, उनकी खाल उतारते या उन्हें पकाते समय, या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से भी यह बीमारी फैल सकती है। बचाव के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है कि वायरस से ग्रसित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। इस बीमारी की पहचान आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे तुरंत आइसोलेट करना चाहिए और त्वचा को सूखा और खुला रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो, चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और लगातार चिकित्सक के संपर्क में बने रहना चाहिए।

भारत में लैंगिक असमानता आज भी

भारत में लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक वेतन अंतर जैसे मुद्दे समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालते रहते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता हासिल करना भारत सहित विश्व भर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से इस असमानता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाएं अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं जैसे- मां, पत्नी, बहन, शिक्षक, दोस्त बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाती हैं। बावजूद क्या कारण है कि आज हमें महिला समानता दिवस मनाये जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। सरकार को अपनी लैंगिकवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा।

भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता के कारण महिला समानता ज्यादा अपेक्षित है। भारत ने महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया, परन्तु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक एवं विसंगतिपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में काफी प्रगति देखी गयी है, खासकर शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-2023 के माध्यम से नारी शक्ति को राजनीति में समानता देने की शुरूआत हुई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों ने समाज में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त, कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। इन प्रगतियों के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

दुनिया भर में, महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा से लेकर राजनीति और आर्थिक भागीदारी तक विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों को तीव्र गति देने के लिये महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1920 में इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन स्वीकार किया गया था। यह दिन महिलाओं को पुरुषों के समान मानने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है, जिसने 1893 में महिला समानता की शुरूआत की। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अब्जुग के प्रयास से 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने इस वर्ष की थीम है समता को अपनाएं, जो न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर केन्द्रित है। यह व्यापक मानवाधिकारों और सतत विकास के साथ लैंगिक समानता के परस्पर संबंध पर जोर देता है।

महिला समानता दिवस से जुड़ा हुआ रंग बैंगनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, बैंगनी रंग महिलाओं और लैंगिक समानता का प्रतीक है। यह न्याय और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, और अक्सर दूरदर्शी सोच और महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। महिलाएं ही समस्त मानव प्रजाति की धुरी हैं। वो न केवल बच्चे को जन्म देती हैं बल्कि उनका भरण-पोषण और उन्हें संस्कार भी देती हैं।

भारत में लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक वेतन अंतर जैसे मुद्दे समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालते रहते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता हासिल करना भारत सहित विश्व भर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से इस असमानता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के खुद के कर्मचारियों में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये अधिक एवं नये अवसर सामने आने जरूरी है। क्योंकि देश में ऐसी महिलाएं नजर आती हैं, जो सभी प्रकार के भेदभाव के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं और सभी उन पर गर्व भी महसूस करते हैं। परन्तु इस कतार में उन सभी महिलाओं को भी शामिल करने की जरूरत है, जो हर दिन अपने घर में और समाज में महिला होने के कारण असमानता, अत्याचार एवं उपेक्षा को झेलने के लिए विवश है। आये दिन समाचार पत्रों में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी खबरों को पढ़ा जा सकता है, परन्तु इन सभी के बीच वे महिलाएं जो अपने ही घर में सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि वह एक औरत है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) नाम के थिंक टैंक ने बताया है कि भारत में केवल 7 प्रतिशत शहरी महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास रोजगार है या वे उसकी तलाश कर रही हैं। सीएमआईई के मुताबिक, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। किसी देश या समाज में अचानक या सुनियोजित उथल-पुथल होती है, कोई आपदा, युद्ध एवं राजनीतिक या मनुष्यजनित समस्या खड़ी होती है तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर स्त्रियों पर पड़ता है और उन्हें ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।

दावोस में हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट **टाइम टू केयर** में घरेलू औरतों की आर्थिक स्थितियों का खुलासा करते हुए दुनिया को चौका दिया था। वे महिलाएं जो अपने घर को संभालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं, वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती है। अगर हम यह कहें कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पेशा है, जिसमें 24 घंटे, सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज क्राइसिस झेलते हैं, हर डेडलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना छुट्टी के। सोचिए, इतने सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसके इस काम को राष्ट्र की उन्नति में योगभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। प्रश्न है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? दरअसल, इस तरह के हालात की वजह सामाजिक एवं संकीर्ण सोच रही है। पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था में आमतौर पर सत्ता के केंद्र पुरुष रहे और श्रम और संसाधनों के बंटवारे में स्त्रियों को हाशिये पर रखा गया है। सदियों पहले इस तरह की परंपरा विकसित हुई, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आज जब दुनिया अपने आधुनिक और सभ्य होने का दावा कर रही है। एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर कब तक सभी वंचनाओं, महामारियों एवं राष्ट्र-संकटों की गाज स्त्रियों पर गिरती रहेगी।

जहां देश में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी और वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर द्रोपदी मुर्मू हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी राज्य की बागडोर संभाल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष भी एक महिला मायावती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तो विश्व की ताकतवर महिलाओं में शुमार किया ही जा चुका है। पूर्व में लोकसभा में विपक्ष की नेता के पद पर सुषमा स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर मीरा कुमार ने भी महिला के गौरव को बढ़ाया हैं। कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्रों में इंदिरा नूई और चंदा कोचर जैसी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण सहित अनेक महिलाओं ने राजनीति में अपनी छाप छोड़ रही है। हमारी सेना में महिलाओं की यथोचित भागीदारी उसे ज्यादा शालीन, सामाजिक, योग्य और कारगर ही बनाएगी।

युगों से आत्मविस्मृत महिलाओं को अपनी अस्मिता और कर्तृत्वशक्ति का तो अहसास हुआ ही है, साथ ही उसकी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व चेतना में क्रांति का ऐसा ज्वालामुखी फूटा है, जिससे भेदभाव, असमानता, रूढ़संस्कार जैसे उन्हें कमतर समझने की मानसिकता पर प्रहार हुआ है। पुरुषवर्ग महिलाओं को देह रूप में स्वीकार करता है, किन्तु आधुनिक महिलाओं ने अपनी विविधआयामी प्रतिभा एवं कौशल के बल पर उनके सामने मस्तिष्क एवं शक्ति बनकर अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है, वही अपने प्रति होने वाले भेदभाव का जबाव सरकार, समाज एवं पुरुषों को देने में सक्षम है, महिला समानता दिवस यदि उनकी सक्षमता को पंख दे रहा है तो यह जागरूक एवं समानतामूलक विश्व-समाज की संरचना का अभ्युदय है।

अपने वालिद की परम्परा को बनाए रखा फिराक ने

28 अगस्त, 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्में रघुपति सहाय बचपन से ही शायरी से हद दर्जे के लगाव और मोहब्बत के चलते फि राक गोरखपुरी हो गए। उन्होंने अपना यह तखल्लुस क्यों चुना?, इस-ाका भी एक मुख्तसर सा कि स्सा है, जो उन्होंने मौलाना खैर बहोरवी के नाम लिखे अपने एक खत में वाजेह किया था। इस खत में फि राक लिखते हैं, 'वे 'दर्द' देहलवी के कलाम से काफी मुतास्सिर'थे। 'दर्द' के उत्तराधिकारी नासिर अली 'फिराक' थे। चूंकि वे भी 'दर्द' देहलवी के कलाम के मद्दाह थे, लिहाजा उन्हें यह तखल्लुस खूब पसंद आया और उन्होंने भी अपना तखल्लुस 'फिराक' रख लिया।' 'फिराक' तखल्लुस पसंदगी की एक और वजह शायद इस लफ़्ज के मायने भी हैं, जो उनकी शख्सियत से काफी मेल खाते हैं। गोरखपुर में पैदाइश की वजह से उनका पूरा नाम हुआ, फि राक गोरखपुरी। बहरहाल, फि राक के वालिद मुंशी गोरख प्रसाद खुद एक अच्छे शायर थे और उनका तखल्लुस ह्यइबरत' था। वे फारसी के आलिम थे और उर्दू में शायरी करते थे। जाहिर है कि घर के अदबी माहौल ने फि राक के मासूम जेहन पर भी असर डाला। वे भी शायरी के शौकीन हो गए। बीस साल की उम्र आते-आते वे भी शे'र कहने लगे। शुरूआत में उन्होंने फारसी के उस्ताद महदी हसन नासिरी से कुछ गजलों पर इस्लाह ली। बाद में खुद के अंदर ही शे'र कहने की इतनी सलाहियत आ गई कि किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ी।

फिराक गोरखपुरी की गजलों-नज्मों में फारसी, अरबी के ही कठिन अल्फ़ज नहीं होते थे, बल्कि कई बार अपने शे'रों में उस हिंदुस्तानी जबान को इस्तेमाल करते थे, जो हर एक के लिए सहल है। मिसाल के तौर पर उनके कुछ इस तरह के शे'र हैं, 'तुम मुखातिब भी हो, करीब भी तुमको देखें कि तुमसे बात करें।', 'मुहब्बत में मिरी तन्हाइयों के हैं कई उन्वां/तिरा आना, तिरा मिलना, तिरा उठना, तिरा जाना।' फि राक ने श्रंगार रस में डूबी अनगिनत गजलें भी लिखीं। जब इनसे दिल भर गयो, तो रुबाइयात लिखीं, नज्में लिखीं। पचास साल से ज्यादा वक्त की अपनी अदबी जिंदगी में फि राक गोरखपुरी ने तकरीबन 40 हजार अशआर लिखे । जिंदगी के आखिरी वक्त तक उनका लेखन नहीं छूटा। वे आखिरी समय तक एकेडमिक और अदबी महफि लों की रौनक बने रहे। फि राक जैसी शोहरत बहुत कम शायरों को हासिल हुई है। श्आने वाली नस्लें तुम पर फख करेंगी हम-असरो/जब भी उन को खयाल आयेगा कि तुम ने 'फि राक' को देखा था।' फि राक गोरखपुरी के इस शे'र में भले ही उनकी खुद-एतिमादी (आत्मविश्वास) और खुदी (अह-ंवाद) दोनों एक साथ झलकती है, लेकिन जिन लोगों ने भी उन्हें देखा-पढ़ा-सुना है, उनका इस शे'र पर मुकम्मल ईमान है। यही वह खास बात है, जो फि राक गोरखपुरी को दीगर शायरों से जुदा करती है।

एक उम्दा मोती, खुश लहजे के आसमान के चौदहवीं के चाँद और इल्म की महफि ल के सद्र ।

जहानत के काफिले के सरदार। दुनिया के ताजदार । समझदार, पारखी निगाह, जमीं पर उतरे फरिश्ते, शायरे-बुजुर्ग और आला। अपने फि राक को मैं बरसों से जानता और उनकी खासियतों का लोहा मानता हूं। इल्म और अदब के मसले पर जब वह जबान खोलते हैं, तो लफ्ज और मायने के हजारों मोती रोलते हैं और इतने ज्यादा कि सुनने वाले को अपनी कम समझ का एहसास होने लगता है। वह बला के हुस्नपरस्त और कयामत के आशिक मिजाज हैं और यह पाक खासियत है, जो दुनिया के तमाम अजीम फनकारों में पाई जाती है।' यह मुख्तसर सा तआरुफ अजीम शायर फि राक गोरखपुरी का है। उनके दोस्त शायर-ए-इंकलाब जोश मलीहाबादी ने अपनी आत्मकथा 'यादों की बरात' में फि राक का खाका खींचते हुए उनके मुताल्लिक यह सब बातें कहीं हैं। जिन लोगों ने भी फि राक को देखा, पढ़ा या सुना है, वे सब अच्छी तरह से जानते हैं कि फि राक गोरखपुरी की शख्सियत इन सबसे कमतर नहीं थी, बल्कि कई मामलों में, तो वे इससे भी कहीं ज्यादा थे। फि राक जैसी शख्सियत, सदियों में एक पैदा होती है। फि राक गोरखपुरी का खाका लिखते वक्त जोश मलीहाबादी यहीं नहीं रुक गए, बल्कि इसी मजामीन में उन्होंने डंके की चोट पर यह एलान भी कर दिया, 'जो शख्स यह तस्लीम नहीं करता कि फि राक की अजीम शख्सियत हिंदुस्तान के माथे का टीका और उर्दू जबान की आबरू, शायरी की मांग का संदल है, वह खुदा की कसम पैदाइशी अंधा है।' फि राक गोरखपुरी की सतरंगी शख्सियत का इससे बेहतर तआरुफ शायद ही कोई दूसरा हो सकता है।

फिराक की इब्तिदाई शायरी यदि देखें, तो उसमें जुदाई का दर्द, गम और जज्बात की तीव्रता शिद्दत से महसूस की जा सकती है। अपनी गजलों, नज्मों और रुबाईयों में वे इसका इजहार बार-बार करते हैं

'वो सोज-ओ-दर्द मिट गए, वो जिंदगी बदल गई / सवाल-ए-इश्क है अभी ये क्या किया, ये क्या हुआ।' वे अपने जाती दर्द को इन अल्फाज में आवाज देते हैं, 'उम्र फि राक ने यों ही बसर की / कुछ गम-ए-जानाँ, कुछ गम-ए-दौरा ।

जुदाई के दर्द के अलावा उनके अशआर में 'रात' एक रूपक के तौर पर आती है। उनके कलाम का एक हिस्सा ऐसा है, जिसकी बिना पर उन्हें शायर- ए-नीमशबी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर उनके कुछ ऐसे ही अश्आर हैं, उजले-उजले से कफन में सहर-ओ-शाम 'फिराक' /एक तस्वीर हूँ मैं रात के कट जाने की।' 'तारीकियाँ चमक गयीं आवाजे-दर्द से / मेरी गजल से रात की जुल्फेसँवर गयीं।' फि राक गोरखपुरी हालाँकि अपनी गजलों और मानीखेज शे'र के लिए जाने जाते हैं, मगर उन्होंने नज्में भी लिखी। और यह नज्में, गजलों की तरह खूब मकबूल हुईं। 'आधी रात', 'परछाइयाँ' और 'रक्स-ए-शबाब' वे नज्में हैं, जिन्हें जिगर मुरादाबादी, जोश मलीहाबादी से लेकर अली सरदार जाफरी तक ने दिल खोलकर दाद दी। 'दास्तान-ए-आदम', 'रोटियाँ', 'जुगनू', 'रूप', 'हिंडोला' भी फि राक की शानदार नज्में हैं, जिनमें उनकी तरक्कीपसंद सोच साफजाहिर होती है। 'हिंडोला' नज्म में तो उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब की शानदार तस्वीरें खींची हैं। हिंदू देवी- देवताओं, नदियों, त्यौहारों, रीति-रिवाजों और अनेक मजहबी समाजी यकनिों का इजहार इस नज्म में उन्होंने बड़े ही खूबसूरती से किया है। उर्दू आलोचकों ने इस नज्म को पढ़कर, बेसाख्ता कहा, श्यह नज्म हिंदुस्तानियत की बेहतरीन मिसाल है। इस नज्म में मकामी रंग शानदार तरीके से आए हैं।' फि राक गोरखपुरी के एक और समकालीन फैज अहमद फैज ने अपने एक मजमून में उनके कलाम की तारीफ करते हुए कहा था, 'फि राक साहिब जज्बात व एहसासात की बारीकबीनी में इजहार के ढंग के बारे में कशीदाकारी के माहिर थे। इस लिहाज से कुल्ली तौर से न सही, बहुत हद तक उनका सौदा' और 'मीर' से मुकाबला कर सकते हैं।'

रोड टु स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का हुआ शुभारम्भ

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग, अश-ोक लीलैण्ड लि. एंव लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा अशोक लिलैण्ड लि. एवं लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा लगाई गयी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही बच्चों को अन्नप्रासन कराया तथा स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षिक किट वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र के लिए सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है, शिक्षा किसी भी सभ्य, समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के लिए एक बुनयादी आवश्यकता होती है। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नही की जा सकती है और इसी लिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्व सुलभ कराने हेतु मंथन चलता रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग प्रयास हुए है। भारत के प्राचीन गुरूकुल में जो उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए है वह भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। भारत के प्रसिद्ध नालन्दा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय काशी या कान्चीपुरम के विद्या के केन्द्र, जहां पूरी दुनिया से आकर लोग अध्ययन करते थे, यह सभी केन्द्रों के माध्यम से उज्जवल भविष्य के लिए एक मंथम का कार्यक्रम चलता रहा लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते चले गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लार्ड मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तो सबसे पहले उसने पूरे भारत के अन्दर भ्रमण किया और उसके बाद उसने ब्रिटिश वायसराय को पत्र लिखा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं, भारत एक ऐसा देश है, जहां की पंचायतें, संस्थाएं स्वंय भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति अग्रणी बनाकर साक्षरता के शत प्रतिशत लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध दिख रही है और भारत ही दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला कि मै भारत में किसी भी क्षेत्र में गया तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए दिखाई दिये, कोई भी अपने घर में ताला नही लगाता है, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है, और भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिश गुलाम बनाकर नही रख सकते है। इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा नीति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में देखा जाये तो देश के अन्दर निरक्षरता बढ़ी लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारम्भ हुए उसके कुछ परिणाम भी प्राप्त हुए इस पर और कुछ किये जाने की आवश्यकता है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, इस बीमारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की एक नई आधाशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देशवासियों को दी।

उन्होंने कहा कि हम लोंगो ने 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारम्भ किया था। स्कूल चलों अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया अकेले उ.प्र. के अंदर हम लोंगो ने देखा की लगभग 58 से 60 लाख नये बच्चों का नामांकन हुआ। कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित थी लेकिन उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 34 लाख से बढ़कर छात्रों की संख्या 1 करोड़ 92 लाख की संख्या यह बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नही बन पा रहा था। बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ा सके इसके लिए सरकार ने प्रयास प्रारम्भ किया। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में ज्यादा रूचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नही भेजते थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगे उन बच्चों के लिए यूनीफार्म, स्वेटर, बैग, बुक्स के साथ उन बच्चों को जूता मोजा भी उपलब्ध कराया जायेगा। आज प्रदेश सरकार ने 1200 रुपए इन छात्रों के लिए यूनीफार्म, बैग और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है। जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। हमने जनप्रतिनिधियों, समाज के नागरिको से सहयोग लेकर आपरेशन कायाकल्प का एक अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया। आपरेशन कायाकल्प के माध्यम बडी संख्या में विद्यालयों मे फर्श,फर्निचर, स्मार्ट क्लास बनाने, बालक, बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, लाईब्रेरी बनाने, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था सुदृढ़ करने और अन्य कई कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। आज उसका परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। इसमें केवल सरकार ही नही पहले की तरह कई संस्थाओं का योगदान मिला जो सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते है। उन्होंने अशोक लीलैण्ड, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि चरगावां और भटहट विकास खण्ड को रोड टू स्कूल कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अभिनव प्रयास में इन्होंने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम यह एक स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। स्कूल चलो अभियान में शिक्षक घर घर जाते है और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल में लाने का प्रयास करते है। रोड टू स्कूल में जो बच्चे ड्राप आउट कर लिए या स्कूल नही जा रहे है इसमें एक पिरामिड तैयार किया है जिसमें रिसोर्स पर्सन द्वारा टाप टू बाटम मानीटरिंग करने वाली टीम इन बच्चे पर समीक्षा कर बेसिक शिक्षा परिषद के साथ उन्हें रोड टू स्कूल कार्यक्रम से जोडेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस मॉडल शिक्षा के द्वारा बच्चे गणित की पहेली को समझेंगे और उन्हें आगे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नही करना पड़ेगा बड़ी सरलता से चीजो को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग अनवरत रूप से इसको आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है। और इसके अन्य संस्थाओं को जिसमें कम्पोजिट विद्यालायों को भी इस नये तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है यह अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शतप्रतिशत बच्चों का नामांकन भी कराना है और उन्हें स्कूल तक भी लाना है और उन्हें योग्य बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से जोड़ना है। एक व्यक्ति के आत्म निर्भर बनने से समाज आत्म निर्भर होगा, समाज के आत्म निर्भर बनने से राष्ट्र आत्म निर्भर होगा, और राष्ट्र के आत्मिनिर्भर बनने से भारत दुनिया में उभरती हुई ताकत के रूप में खड़ा होगा और फिर भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नही रोक सकता है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस बीमारी के कारण पूर्वी उ.प्र. में हजारों बच्चे प्रभावित होते थे, स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ उ.प्र. शासन और भारत सरकार के सभी अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या के समाधान का रास्ता निकाला है और आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य, खेल, कला के कार्यक्रम इसमें सम्मलित किये गये है। इसमें बुनियादी शिक्षा के सुधार के कार्य किये गये हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक, भावनानात्मक, सामाजिक और पारिवारिक कल्याण से सम्बंधित पाठ्यक्रम इसमे तैयार किये गये है। खेलों इंडिया पाठ्यक्रम इसके माध्यम से इसमें क्रियान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोर टू स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से दो विद्यालयों के लिए एक रिसोर्स पर्सन, चरगावां और भटहट दोनो विकास खण्डो में लगभग 50-50 रिसोर्स पर्सन अशोक लिलैड लि. तथा लर्निंग लिंक्स फाउण्डेशन के द्वारा तैयार किये जायेंगे और इसके साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड में 05 सीनियर रिसोर्स पर्सन की भी तैनाती की जायेगी और एक सीनियर रिसोर्स के अन्तर्गत 15-15 विद्यालय होंगे। इसमें 5 प्रोजेक्ट एशोसिएट भी तैनात किये जायेंगे। एक प्रोजेक्ट एशोसिएट के अन्तर्गत 15-15 विद्यालय होंगे। इसके माध्यम से हमें नयी शिक्षा नीति के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति जिसमें निपुण भारत की कल्पना की गयी है।

बेसिक शिक्षा परिषद को इसे सफलता पूर्वक हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के स्तर में सुधार के नये नये प्रयास हो रहे है। रोड टू स्कूल का ही एक नया रूप हमें अटल आव-ासीय विद्यालय के रूप में दिख रहा है जिसमें रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चे व निराश्रित बच्चों को प्रवेश दिया गया है ऐसे 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रारम्भ हो चुके है और 57 अन्य जनपदों में खोलने की तैयारी चल रही है इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में सभी जनपदों में नये स्कूल की तर्ज पर बनाने की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे है। पीएम श्री विद्यालय को भी हर विकास खण्ड स्तर पर स्थापित करने की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। ये अमूल चूल परिवर्तन नये भारत को एक विकसित भारत बनाने में सफल होगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्होंने शिक्षको से अपील करते हुए कहा कि आप नये भारत के निमार्ता है, और देश व दुनिया आपको देख रही है तथा अपने आपको अपडेट करना होगा। हम जिस विषय के शिक्षक हो उसमें महारत रखनी होगी और साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी रखनी होगी जिससे हम बच्चों को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सके। तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए कैसे हम इस तरीके को अपना सकते है ये भी जनाकारी रखनी होगी। अगर हम इस प्रकार अपने आपको तैयार कर पायेंगे तो याद रखिए की हम शिक्षा को इतना सशक्त कर देंगे कि आने वाली पीढी इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी और जीवन वही है जो अन्य के लिए यादगार बन सके। आप पर बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य निर्भर करता है क्यो कि आप इन बच्चों का भविष्य बना रहे है और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनायेंगे तो हमारे समाज व देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बिमुख हो जायेंगे तो फिर संक्रमण फैलेगा और हमे संक्रमण को रोकना पड़ेगा और निपुण भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उ.प्र. के निर्माण के लिए अशोक लिलैण्ड व लर्निंग लिंक फाउण्डेशन जैसी संस्थाए सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है इनके भविष्य को उज्जवल बनाकर भारत के भविष्य को उज्जवल और विकसित भारत की परिकल्पना को स-ाकार करने में सफल होंगे।

कारपोरेट सेगमेंट सर्वेक्षण-2024 कार्यक्रम संबंधी जानकारी समय से उपलब्ध कराएं: जिलाधिकारी

गोरखपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने आम जनमानस को अवगत कराया है कि शिक्षा, चिकित्सा एवं सेवा क्षेत्र के कारपोरेट सेगमेंट सर्वेक्षण 2024 का सर्वेक्षण कार्य जनपद में अगस्त एवं सितम्बर माह में सम्पन्न किया जाना है। यह सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र. लखनऊ के द्वारा अर्थ एवं संख्या अधिकारी के जनपद कार्यालय के माध्यम से किया जाना है। सर्वेक्षण हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों यथा गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, संतकबीरनगर, बस्ती एवं आजमगढ़ जनपद से 33 सर्वेक्षक एवं पर्यवेक्षक की सूची तैयार कर ली गयी है। जिनके द्वारा उक्त सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 271 इकाईयों का, चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 137 इकाईयों को एवं सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 349 इकाईयों को सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत सम्बंधित इकाई से अनुसूची में खण्डवार सूचना भरी जायेगी।

उन्होंने बताया कि शासन के मंशानुसार उ.प. की अर्थ व्यवस्था को 01 ट्रिलियन डालर तक ले जाने हेतु आर्थिक क्रियाकलाप में अधिक से अधिक जानकारी आवश्यक है। उक्त सर्वेक्षण से तीनो सेक्टर से चयनित इकाईयों को जीवीए आंकलन करना सम्भव हो सकेगा। जनपद के सभी शिक्षा, चिकित्सा एवं सेवा क्षेत्र के कारपोरेट सेगमेंट इकाईयों के मालिक/प्रबंधक उक्त सर्वेक्षण कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए सर्वेक्षक को सम्बंधित इकाई का आंकड़ा उपलब्ध अवश्य कराये ताकि उक्त सर्वेक्षण कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया जा सके। यह सर्वेक्षण शासन की प्राथकिता में सम्मिलित है। अतः सूचना देने में कोई भी लापरवाही/विलम्ब न करें।

जनपद न्यायाधीश ने किया औचक निरीक्षण

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वन के क्रम में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में गत 21 अगस्त को जिला कारागार, गोरखपुर का औचक निरीक्षण विकास सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा किया गया।

निरीक्षण दौरान अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर विकास सिंह के साथ ही साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, उपस्थित रहें। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव द्वारा पाकशाला, पाठशाला, नव निर्मित महिला बैरक, पुरूष बैरक, चिकित्सालय व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया।

समक्ष आयी कमियों के सुधार हेतु वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

साथ ही साथ जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध पुरूष एवं महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी है एवं वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह बीमार सभी बंदियों को विशेष रूप से ध्यान रखें एवं नियमित रूप से बैरक की साफ-सफाई करवाते रहे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रपत्र के द्वारा कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बन्दियों की रिहाई हेतु चलाये जा रहे अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के अन्तर्गत जिन बंदी के पास अधिवक्ता नही है या ऐसे बंदी जो जमानतदार के अभाव में अभी तक जेल में निरूद्ध है, का प्रार्थना पत्र तैयार कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करावे जिस-ासे उक्त बंदी के मुकदमें में अधिवक्ता नियुक्त हो सकें। उक्त जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी है।

पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा केन्द्रों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण

गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने पुलिस उप महानिरीक्षक आनंद सुरेशराव कुलकर्णी के साथ जनपद में चल रही उ.प. पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन, अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज तथा नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया का निरीक्षण कर केन्द्रों की व्यवस्था को देखा। निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों के कक्षों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं की गहन जांच किया और कक्ष निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपनी ड्यूटी पर अलर्ट मोड पर रहें इसपर लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने सभी केन्द्रों के कंट्रोल रूम में जाकर प्रत्येक कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी जांच किया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया है, इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी संदिग्ध नहीं मिला।

मंडलायुक्तकी समीक्षा बैठक, उपनिदेशक को काराणबताओ नोटिस

गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम डैशबोर्ड से संबंधित समीक्षा बैठक करते हुये कृषि विभाग के कार्यों में सन्तोषजनक प्रगति न होने पर उपनिदेशक कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास/निर्माण कार्यों में विभाग आपसी समन्वय स्थापित करके यथाशीघ्र समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करें, इस पर किसी भी तरह की शिथिलता/लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो और कोई भी पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रह पाये। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने आयुक्त सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम डैशबोर्ड से संबंधित मण्डल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिया।

उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विद्युत बिलों में सुधार, लाइन लॉस/एटीएनसी नुकसान कम करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने तथा नए कनेक्शन के आवेदनों का निस्तारण समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अन्तर्गत मण्डल में सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है, उसे

ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें, तथा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उन्होंने हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा आंकलन, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण तथा मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुये संबंधित विभाग को प्रगति लाने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पशुधन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग आदि विभिन्न विभागो की समीक्षा करते हुये कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को मण्डल में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु मंडल के सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्ष-ाकों तथा नोडल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इससे संबंधित सभी तैयारियां ससमय पूरी कर लें और सभी अधिकारियों को ड्यूटी प्वाइंटों पर अलर्ट कर दें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने मंडल की बाढ़ से संबंधित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को बाढ़ समितियां व बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश एवं वर्चुअल माध्यम से देवरिया, कुशीनगर तथा महाराजगंज के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

निर्वाचक नामावलियों की प्रकाशन तिथि घोषित

गोरखपुर। अपर जिलाधिकारी (वि.रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर 2024 तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख्स भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का आयोग की अनुमति के बिना उक्त पुनरीक्षण अवधि में 29 अक्टूबर 2024 से 06 जनवरी 2025 तक स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है।

जम्मू-कश्मीर में पहला बड़ा इम्तिहान

जम्मू-कश्मीर में सितंबर माह तक चुनाव कराए ही जाने थे, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ' का आदेश था यह विधानसभा चुनाव जम्मू- कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव को पहली बड़ी परीक्षा होगी। चुनाव इस क्षेत्र में राजनीतिक भावना का एक प्रमुख संकेतक होंगे जो पिछले एक दशक में व्यापक बदलावों से गुजरा है। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था तब 87 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे. परिसीमन के बाद अब वहीं 90 सीटें हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में 65.52 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में 65.52 का हाई बेटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी 1 पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जबकि भारतीय जनता । पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। डॅ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थीं और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें डॅ आई थीं। सात सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के पास गई थीं। हालांकि 87 सीटों डॅ वाली विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके चलते गठबंधन डॅ सरकार बनी थी। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू- कश्मीर एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 90 सीटों के लिए । तीन चरण के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। 2014 के चान्द ने पहली बार होगा जब जम्मू-कश्मीर । की जनता विधानसभा चुनाव में मतदन करेगी 2022 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इसमें कश्मीर घाटी में और जम्मू में 43 सीटें शामिल हैं।

जम्मू कश्मीर में जनादेश का यह समय 110 लंबे सालों के बाद आ रहा है, लेकिन कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। संसद 5 डॅ अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त कर चुकी है, लिहाजा जम्मू- कश्मीर का 'विशेष दर्जा समाप्त हो चुका है। अब वह भी देश के अन्य राज्यों और संघ डॅ शासित क्षेत्री सरीखा सामान्य क्षेत्र है। पुराना राज्य से भागों में विभाजित कर दिया गया था, डॅ लिहाजा राज्यत्व भी एक प्रमुख मुद्दा है। अब एक तरफ जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ लाख अलग होकर केंद्र शासित क्षेत्र है। अब सितंबर-अक्टूबर में जी विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, वे इन ऐतिहासिक बदलावों के संदर्भ में होंगे। आतंक से मिले गहरे घावों और असहनीय पीड़ा के बीच इस बात का संतोष और खुशी है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र फिर से लौट रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत हो रही है।

प्रधानमंत्री का त्रि-दिवसीय यूक्रेन-पोलैण्ड दौरान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तीन दिन के विदेश दौरे पर हैं। पीएम दो दिन पोलैंड में गुजारने के बाद एक दिन के लिए रूस के साथ युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन भी जाएंगे। इस लिहाज से पीएम का विदेश दौरा खास है। खास बात ये भी है कि युक्रेन में युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से युक्रेन को यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे जो लगभग 10 घंटे लंबी होगी। प्रधानमंत्री बुधवार से शुरू हुई दो दिवसीय पोलैंड यात्रा के दौरान चारसों हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सबसे पहले 'नवानगर के जाम साहब स्मारक पर श्रद्धांजलि देने गए।

वह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 45 साल बाद पोलैंड का दौरा है। वे पोलिश प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण समझौतों के साथ साथ साथ पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को भी सम्बोधित करेंगे। भारत पोलैंड के साथ गहरी दोस्ती को महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच संबंध लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता से और मजबूत हुए हैं। मोदी का स्वागत करते हुए पोलैंड के चार्ज डि अफेयर्स सेबास्टियन डोमजालस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन बुद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और नूक्रेन दौरा वैश्विक समुदाय को एक बड़ा संदेश देगा। इस दौर से संदेश जाएगा कि भारत शांति, संवाद, युएन चार्टर और देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास करता है। प्रधानमंत्री का यह विदेश दौरा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत ने वैश्विक स्थिरता लाने के अपने प्रवासों में कोई कटौती नहीं की है। इसीलिए रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ आव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। जहां वे राष्ट्रपति बोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और देश में शांति और स्थिरता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देंगे। उधर पीएम मोदी का पोलैंड दौरा मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार होने के लिहाज से भी अहम है। भारत ने मॉस्को के साथ व्यापार जारी रखते हुए बातचीत और कूटनीति का रुख बनाए रखते हुए, पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने को कोशिश की है। रूस के साथ संघर्ष के बाद और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लगभग एक महीने बाद युद्धस्त यूक्रेन में यह मोदी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति बलोडिनिर जेलेंस्की के कार्यालय ने भी एक बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया, 23 अगस्त को दूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन को आधिकारिक यात्रा करेंगे। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति क्लोडिमिर जेलेस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। यह भी उम्मीद है कि युक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे सोवियत संघ के पतन के बाद 26 दिसंबर 1991 को भारत द्वारा यूक्रेन को एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 17 जनवरी 1992 युक्रेन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापना पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7 मई, 1992 कीव में भारतीय दूतावास स्थापित किया गया था। रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में भारत यूक्रेन के हितों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है जबकि सारी दुनिया रूस के साथ भारत के पुराने और महत्वपूर्ण संबंधों की गवाह है। नाटो सहित दुनिया के विभिन्न देश प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

विश्व में एपीआई के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान

विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी-कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं आरटीफिशियल इंटेलिजेन्स का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में स्वदेशी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा 1.27 लाख करोड़ रुपए की रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 16.7 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाईयों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त वर्णित उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 79.2 प्रतिशत का रहा है जबकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 20.8 प्रतिशत का रहा है। हर्ष का विषय तो यह भी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में निर्मित किए जा रहे उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निर्मित होती जा रही है और इन उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है और यह भारत में रक्षा के क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। निर्यात में यह वृद्धि न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते पदचिन्हों को दशार्ती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दशार्ती है। भारत में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई रणनीतिक पहल भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जैसे, मजबूत नीतिगत ढांचे को विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का असर भी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में हो रही भारी भरकम वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर भी अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति को लागू करने से देश में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में आज भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है और वह अपने रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16-18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि हाल ही के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाईयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

रक्षा क्षेत्र की तरह ही, हाल ही के समय में भारत ने उत्पादन के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अढक (ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडीयंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरे तौर पर चीन से आयात किया जाता था। परंतु, कोरोना महामारी के दौरान भारत को यह अहसास हुआ कि यदि चीन इस कच्चे माल का निर्यात भारत को करना कम कर दे अथवा बंद कर दे तो भारत में तो दवा उद्योग की इकाईयों में निर्माण कार्य ही ठप्प पड़ जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने अढकके उत्पादन को भारत में ही करने का फैसला लिया, आज स्थितियां पूर्णतः बदल गई है एवं अढकका निर्माण भारत में ही किया जाने लगा है। सम्भव है कि आगे आने वाले कुछ समय में अढकके निर्माण के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। भारत आज अढक के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है एवं भारत की वैश्विक अढकउद्योग में 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी बन गई है। आज भारत में 500 से अधिक प्रकार के विभिन्न अढकका उत्पादन किया जा रहा है। भारत में अढकका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दवा उद्योग में तेज गति से वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है और आज यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.72 प्रतिशत का योगदान देने लगा है एवं दवा उद्योग आज देश में रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित कर रहा है। भारतीय दवा उद्योग के वर्ष 2024 के अंत तक 6,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2013-14 के बाद से वर्ष 2021-22 तक भारतीय दवा निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे भारत को अब ब्लविश्व का फामेर्सी हबब्ब भी कहा जाने लगा है। केंद्र सरकार अढक के उत्पादन को भारत में बढ़ाने के उद्देश्य से एक समग्र एवं अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करने पर जोर दे रही है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने अढक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 6,940 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। 35 सक्रिय दवा सामग्री का विनिर्माण, जो अढक का लगभग 67 प्रतिशत है, जिसके लिए भारत की 90 प्रतिशत आयात पर निर्भरता है, भारत में ढछकयोजना के तहत प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2022 के बाद से भारत के फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव आया है एवं भारत अब वॉल्यूम उत्पादक से एक मूल्यवान आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दवाई के क्षेत्र में भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हो गया है। लगभग 4 वर्ष पूर्व वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की उपलब्धतता में आई भारी कमी के चलते वाहनों के उत्पादन को भारी मात्रा में घटाना पड़ा था। परंतु, इसके बाद केंद्र सरकार ने यह बीड़ा उठाया था कि सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार 2,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने की सम्भावना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं एवं सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाईयां भारत में अधिक से अधिक संख्या में स्थापित हों इसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वैश्विक स्तर पर कई प्रौद्योगिकी फर्म से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए सीधे ही चर्चा भी कर चुके हैं। काउंटरपोईंट रीसर्च और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसीएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक लगभग 6,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा जो वर्ष 2019 के बाजार से तीन गुना अधिक होगा।

गिरोह रूपी राजनीतिक जातियों की क्रोनोलॉजी समझें

हाँ ! तो अब गिरोह की क्रोनोलॉजी समझिए और बांट दीजिए समाज को । मतलब कुछ दलित चाहे बड़ी बड़ी कोठियां बंगले बना ले , लाखों करोड़ों के कारोबार कर ले , पढ़ लिखकर मोटे मोटे पैकेज ले ले , वह दलित बने रहेंगे , उनके बच्चे अखिलेश यादव की तरह विदेश में पढ़े पर आरक्षण के दायरे में ही रहेंगे ? तो ऐसे आएगी समानता और समरसता ? क्रीमी लेयर का मुद्दा तीन दशकों से उठता आ रहा है । अब सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद रास्ता खुला तो राजनीति आड़े आ गई । वोट सबको चाहिएं , बीजेपी को भी तो वो क्यों पीछे हटेगी राजनीति से । चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण, नौकरी के लिए आरक्षण, पढ़ने के लिए आरक्षण, योजना का लाभ लेने के लिए आरक्षण हर चीज में आरक्षण घुस चुका है और इतने पर भी यादि सामाजिक स्थिति में सुधार नही हो रहा तो बिल्कुल कृमीलेयर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सही है कि मलाई खा चुके आरक्षणधारी लोगो को अपने समाज के गरीब लोगो के लिए आरक्षण का त्याग कर देना चाहिए पर विडंबना देखिए कि जिनके हित के लिए कोर्ट नें फैसला दिया उन्ही को बड़े चालाकी से सड़को पर उतार कर भारत बंद के लिए उकसवा दिया गया। गजब का गिरोह है ! जब समाज गिरोहों में बटा होता है तब योग्यता नकार दी जाती है। आज यह यथार्थ है कि समाज नहीं बचा हुआ है गिरोह बचे हुए हैं। कोई गिरोह जाति का है, कोई गिरोह क्षेत्र का है तो कोई गिरोह विचारधारा के नाम पर है, जबकि यथार्थ यह है कि उसमें अधिकांश लोगों में न कोई विचार है और न ही कोई धारा है। कहीं जातियों के नाम पर भयादोहन हो रहा है, तो कहीं क्षेत्र के नाम पर और कहीं विचारधारा, दल और संगठन के नाम पर। राहुल गांधी , लालू यादव , मायावती और अखिलेश कि अपनी थ्योरी ! बांग्लादेश में बर्बर हिन्दू उत्पीड़न के खिलाफ एससी एसटी , ओबीसी या मुस्लिम कोई संगठन प्रदर्शन करने नहीं आया । अब सुप्रीमकोर्ट के क्रीमी लेयर को अलग करने के आदेश के खिलाफ सभी राजनैतिक दलों के दलित एक साथ बाहर निकल आए ? कहते हैं कि 77 सालों में जो दलित करोड़पति हो गए हैं , उन्हें भी आरक्षण का लाभ पूर्व की भांति मिलता रहे । मतलब वे कह रहे हैं कि आरक्षण उनका जन्मसिद्ध अधिकार है । क्रीमी लेयर को किसी भी सूरत में दलित कोटे से अलग नहीं किया जा सकता । दलितों के कईं संगठनों ने बंद का आयोजन किया जो बहुत सफल नहीं रहा । अनुसूचित जातियों के तमाम सांसद और विधायक मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाया जाए और संसद में लाकर क्रीमी लेयर को भी पूर्व की भांति आरक्षण यथावत जारी रखा जाए । याद रहे कि ऐसा ही एक अध्यादेश तब भी लाया गया था जब सुप्रीमकोर्ट ने एससी एसटी कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस जांच का आदेश दिया था । वैसे संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि आरक्षण कब तक रहेगा उसकी अवधि नियत की जानी चाहिए । लेकिन पहले नेहरू और फिर उनकी बेटी इंदिरा ने इसे जारी रखा । उससे भी बढ़कर मंडल आयोग का गठन कर दिया , जिसकी राय कभी नहीं मानी । मंडल आखिर वीपी सिंह के काम आया जिन्होंने पूरे का पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया । तो चलने दीजिए आरक्षण का यह खेल । अभी जातियों को और तोड़िए राहुल गांधी ? एक दिन ये 17.5% अनुसूचित जातियां और 27% ओबीसी ही तुम्हें भी बताएंगे कि संख्या भारी हिस्सेदारी का असली तमाशा क्या है । राहुल गांधी के सिर सेहरा बंधेगा कि उन्होंने आर्यसमाज और संघ के सरनेम विहीन समाज के सिद्धांतों को कैसे ध्वस्त किया । ठीक है , सुप्रीमकोर्ट के क्रीमी लेयर हटाने संबंधी आदेश की धज्जियां उड़ाइए , आदेश को शौक से पलीता लगाइए । बांटिए समाज , बनाइए जातियां , दीजिए आरक्षण पर आरक्षण , आरक्षण में भी आरक्षण ? प्रतीक्षा कीजिए उस दिन की जब जाति जाति करने वालों को जनता ही सही तरीके से बताएगी कि उसकी हैसियत क्या है ? कोई कह रहा है अल्पसंख्यकों की चिन्ता होनी चाहिए, कोई कह रहा है जातियों की चिन्ता होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है हमारे संगठन के कार्यकताओं की चिन्ता होनी चाहिए और इस हर चिन्ता से एक अनियमितता उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मनुष्य और उसकी योग्यता की चिन्ता पर ये सभी चिन्ताएं भारी पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति मे योग्यता तो निरीह होकर केवल मूक है।

पंकज सीबी मिश्रा,
जौनपुर

आरक्षण और भारत बंद

जहां तक आरक्षण में आरक्षण या उपश्रेणी विभाजन का प्रश्न है। केन्द्र की मोदी सरकार ने ही इसके लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। यही नहीं उत्तर प्रदेश में भी वर्ष 2000 में यह कवायद एक कमेटी बनाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किया गया था जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का विभाजन किया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।

एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के सम्बन्ध में संविधान पीठ के आरक्षण में श्रेणी वर्गीकरण के फैसले को लेकर आरक्षण के समर्थक सड़कों पर भारत बंद करा रहे थे वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण को लेकर है। एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिससे अब तक सरकारों द्वारा कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण को गोलमोल करके आरक्षित जाति के लोगों के सामान्य मेरिट में आने के बावजूद उन्हें आरक्षित वर्ग की मेरिट में भेज दिया जाता था और इस प्रकार आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पूर्व भी इसी प्रकार का फैसला उत्तर प्रदेश के एक मामले में दिया था। मध्यप्रदेश की भांति ही यही स्थिति उत्तर प्रदेश में 2018 में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी सरकार द्वारा अपनाया गया था जिसके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर बनी मेरिट सूची को ही रद्द कर दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि वह फिर से नई सूची तीन माह के अन्दर बनाकर पेश करे। सवाल उठ रहा था के सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी या हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सूची बनायेंगी। फिलहाल सरकार ने अपना गोलमोल जवाब दे दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जबकि नई सूची की वजह से पूरा परीक्षा परिणाम ही उलट-पुलट जायेगा जिसके कारण 9 हजार से लेकर 20 हजार तक के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए कहा है कि ओबीसी एससी-एसटी आरक्षण वर्ग के मेधावी छात्राओं को अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य कोटे की सीट पर दाखिला लेने का अधिकार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ ले रहे मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी की सीट पर दाखिला नहीं देने का आदेश दिया था। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्दद कर दिया।

2014 में देश में नए राजनीतिक बदलाव के बाद ऐसा लगने लगा था कि मंडल का प्रभाव कम हो गया है। क्योंकि एक ऐसी सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आयी जिसकी पार्टी आरक्षण के खिलाफ रही है और आरक्षण के मामले पर उसका रवैया ठीक नहीं माना जाता रहा है। यद्यपि यह सरकार भी सर्वाधिक ओबीसी वर्ग के सहयोग से ही आयी थी । यही कारण है कि जब मोदी सरकार आयी तो राजनीतिक विश्लेषकों ने उसे मंडल टू की संज्ञा दे दी। जबकि 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध स्वरूप सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा निकाल कर उसका राजनीतिक मुकाबला करने की ठानी थी और आरक्षण विरोधी आंदोलन को भी उसका अप्रत्यक्ष समर्थन था।

जहां तक आरक्षण में आरक्षण या उपश्रेणी विभाजन का प्रश्न है। केन्द्र की मोदी सरकार ने ही इसके लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया था जिस-की रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। यही नहीं उत्तर प्रदेश में भी वर्ष 2000 में यह कवायद एक कमेटी बनाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किया गया था जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का विभाजन किया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।

आरक्षण समर्थकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर सन्देश देने का काम किया गया है कि सरकार इसके बारे में सोचे और इस फैसले को बदलने के लिए संसद से कानून बनाये। इस बंद का समर्थन सभी विपक्षी पार्टियां कर रही थीं। आरक्षण एक संवेदनशील मसला है जिसके कारण जो पार्टियां दिल से इसे नहीं चाहती हैं उन्हें भी मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ता है। बिहार सरकार ने अपने राज्य में जातीय सर्वे कराकर उसके परिणामों के आधार पर आरक्षण को उन जातियों की संख्या के हिसाब से कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आरक्षण समर्थक संगठन आरक्षण के मामले को संविधान की नौवी सूची में डालने की मांग करते हैं जैसा कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण के बावजूद उसे नौंवी सूची से संरक्षण मिला हुआ है।

दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आहवान और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा उसका समर्थन किया जाना आरक्षण में आरक्षण का निर्धारण का अधिकार राज्यों का दिए जाने के खिलाफ हुए इस भारत बंद ने दिखा दिया है कि अपने अधिकारों के लिए हम सचेत हैं और इसके लिए सड़कों पर भी उतर सकते हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है कि वह इसे किस रूप में लेती है।

सवाल महिला सुरक्षा का

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में कोलकाता कांड में भी उसी तरह की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है जिसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे क्रूर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने वाले कानून लाये जाएं। कालांतर देश में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम अस्तित्व में आया। दरअसल, महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही विशाखा दिशा-निर्देशों के विस्तार के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले साल, देश की शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। साथ ही इससे जुड़ी अनिश्चितताओं की ओर भी संकेत दिया था। इसके उदाहरण के रूप में महिलाओं की 'सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड अक्सर नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की यौन हिंसा के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर परिस्थितियां कितनी असुरक्षित हैं। वह भी इतनी भयावह कि कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ यह सब वीभत्स घट जाता है। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये सुरक्षा अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर विशाखा दिशा-निर्देश जारी करने के सत्ताईस साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिये तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन हेतु गठित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चिकित्सा पेशवरों की सुरक्षा, महिला चिकित्सकों के लिये अनुकूल कामकाजी परिस्थितियां बनाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिये प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि ये सिफारिशें यदि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी साबित हुईं तो किसी भी पेशे में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिये असरकारी साबित होंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक स्तर पर एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। निस्संदेह, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के वक्त तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

यही वजह है कि नई कार्ययोजना बनाते समय इस बात का आकलन करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानून और दिशा-निर्देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में कितने सफल रहे हैं। सही मायनों में कानून बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपालन कितने पारदर्शी व संवेदनशील दृष्टि से किया जाता है। साथ ही विगत के अनुभवों से भी सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

किसी अपराध को अपराध कहने से बचें

महिलाओं के प्रति अपराध दंडनीय

चुनावों से पहले जब हमारे देश के अधिकांश दल अपने-अपने घोषणापत्रों में महिला सुरक्षा के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनका क्या फायदा, जब कि-सी ऐसे अवसर पर आप अपने-अपने दल का मुंह ताकते हुए बयानबाजी करें। अपनी कुर्सी की खातिर किसी अपराध को अपराध कहने से बचें और वे बुद्धिजीवी जो इस लड़की की निर्मम हत्या पर आंखें मूंदे हैं क्योंकि यह उनकी राजनीति के पक्ष में नहीं जाता, आखिर उन्हें कौन-सा इलेक्शन लड़ना है। वोट की चिंता करनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिसे सच कहते हैं, उसका इतना पतन हुआ है कि कोई सच भी बोल रहा हो तो बहुत से लोग अपने-अपने हितों को देखकर उसे झूठ साबित करने पर लग जाते हैं। महिला डाक्टर की हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच में जो कुछ भी पाए, वह लड़की जिसके माता-पिता ने उसे डाक्टर बनाया, उसके परिश्रम ने भी उसका साथ दिया, वह तो अब वापस आने से रही। और तो और उसकी तस्वीरें जगह-जगह दिखाई दे रही हैं। उसका नाम बताया जा रहा है। जबकि कानूनन ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। आज जब बड़ी संख्या में लड़कियां काम-काज के लिए बाहर निकल रही हैं, तब सत्ताधारियों द्वारा उनकी हस्ती को मिटा देने के ऐसे षड्यंत्र क्यों सफल हों। कायदे से तो महिलाओं को अपनी सुरक्षा की आवाज के तहत उन दलों से सवाल पूछने चाहिए। पितृसत्ता-पितृसत्ता चिल्लाइए और जब मौका मिले उसकी आड़ में या अपने-अपने दलों की आड़ में छिप जाइए, यह कितना शर्मनाक है।

पिछले दिनों से कोलकाता में एक महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या चर्चा में है। इसे कोलकाता का निर्भया कांड कहा जा रहा है। निर्भया की दुष्कर्म और हिंसक मारपीट के बाद सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस डाक्टर के साथ अपराध वहां किए गए हैं, जहां वह काम करती थी। क्यों सड़कें, घर, अस्पताल, दफ्तर, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में तेज आंदोलन हुआ था। उस समय सारा विपक्ष निर्भया के समर्थन में उतर आया था। और एक बेहद गरिमामय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव हार गई थीं। लेकिन कोलकाता के केस में ममता बनर्जी की सरकार और विपक्ष का बड़ा तबका अगर-मगर कर रहा है। देशभर में डाक्टरों के स्वतः स्फूर्त आंदोलनों को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि डाक्टरों को बीजेपी का सपोर्टर बताया जा रहा है।

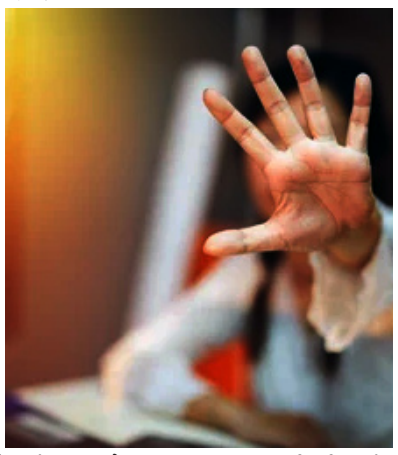

कितने अफसोस की बात है कि शीला दीक्षित को तो बार-बार इस छड़ी से पीटा गया था कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा हुआ। उन्हें निर्भया को श्रद्धांजलि देने तक से रोक दिया गया था। लेकिन बंगाल के मामले में लोगों ने चुप्पी साध रखी है। यही नहीं, निर्भया के बारे में जो तर्क दिए गए थे कि वह इतनी रात बाहर निकली ही क्यों थी। जैसे कि लड़कियां रात में बाहर निकलेंगी तो पुरुषों को यह अधिकार मिल जाएगा कि उनके साथ कुछ भी करो। दुष्कर्म करो, उन्हें मार डालो।

कोलकाता में भी ऐसे ही तर्क सत्ताधारी दल के द्वारा दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह लड़की सेमिनार रूम में उस वक्त क्या कर रही थी। अपराधी से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे कि वह वहां क्या करने गया था। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। महिला डाक्टर को इस बारे में पता चल गया था, वह इसकी शिकायत भी करना चाहती थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। सच जो भी हो, लेकिन एक स्त्री ने वहां जान गंवाई है, जहां वह काम करती थी। आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की क्यों नहीं थी। उसके माता-पिता को तीन घंटे तक उसके शव को क्यों नहीं देखने दिया गया। अज्ञात लोगों ने बड़ी संख्या में आकर अस्पताल में तोड़-फोड़ क्यों की। बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ कोलकाता के सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से हो रही है। क्या सचमुच हमारे राजनेता, जिनमें स्त्री हों या पुरुष, अपनी-अपनी सत्ता बचाने के लिए इतने अमानवीय हो गए हैं। औरतें सहज शिकार हैं और उनसे कोई सहानुभूति भी नहीं। निर्भया कांड के बाद नए रेप कानून की मांग की गई थी कि उसे इतना कठोर बनाया जाए कि अपराधियों की रूह कांपे। कानून बना, मगर ऐसा हो नहीं सका है। सोचें कि जब पढ़ी-लिखी स्त्रियों के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है, तो उन गरीब स्त्रियों का क्या, जिनकी पहुंच न पुलिस तक होती है, न कानून तक। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की पोस्ट पढ़कर तो लगता है कि ये भी इंसान कहलाने के लायक नहीं।

एक आम तर्क यह दिया जा रहा है कि कोलकाता पर बोलने वाले उत्तराखंड के दुष्कर्म पर क्यों नहीं बोले, मणिपुर पर क्यों चुप रहे। मान लीजिए कि कोई उस वक्त नहीं बोला, तो क्या इस वक्त उसने अपने बोलने के अधिकार को किसी के पास गिरवी रख दिया कि जब आपकी राजनीति को सूट करे तब आपसे पूछकर कोई बोले। देश में इन दिनों या तो आप पक्ष में हो सकते हैं, या विपक्ष में। बीच की वह रेखा मिटा दी गई है जहां जब कोई दल अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ की जाए और बुरा करे तो निंदा। आखिर काम-काज की जगह पर स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से क्यों बचना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या महिला और महिला के दुष्कर्म में फर्क होता है। महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हों, देश में किसी भी सत्ताधारी दल की सरकार हो, वह निंदनीय है। लेकिन उंगली अक्सर दूसरे की तरफ ही उठती है।

दफ्तरों में यौन प्रताड़ना की निगरानी करने वाली कमेटियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महिला सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थीं। क्या कोलकाता की डाक्टर के साथ हुआ अपराध इस श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली में जब एक महिला की घर से कुछ दूर रात में हत्या कर दी गई थी, तब से यह कानून बनाया गया था कि रात में जो कैब महिला को छोड़ने जाएगी, वहां उसके साथ दफ्तर का कोई आदमी होगा, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, जब तक महिला अपने घर के अंदर नहीं चली जाएगी, तब तक कैब वहां से नहीं जाएगी। डाक्टर जो बहत्तर-बहत्तर घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें सड़क पर तो छोड़िए, अपने काम-काज के स्थान पर सुरक्षा न मिले तो यह कितनी खतरनाक बात है। बहुत-सी महिला डाक्टरों के बयान इस लेखिका ने पढ़े और सुने हैं। उनमें यही चिंता झलक रही थी। लेकिन कुछ दल और उनके समर्थकों को इससे क्या। वे इन महिला डाक्टरों के बयानों से आंखें मूंदकर, ममता बनर्जी का पक्ष लेते रहे।

इतिहास को बदलने में बलिया की अहम भूमिका

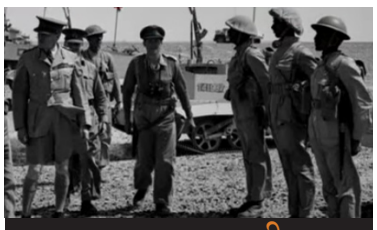

अगस्त का महीना हमारीआजादी के इतिहास को ही समेटे नहीं है, बल्कि इस महीने के साथ कई क्र-ांतियों का गौरवमयी इतिहास भी समाहित है। तारीख में उन घटनाओं को तवज्जो तो मिली है लेकिन भावी इतिहास के संदर्भ में उनके प्रभाव को अहमियत नहीं दी गई है।

बयालिस के आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों का दमनचक्र हर उस इलाके में पूरी क्रुरता के साथ चला, जहां के लोगों ने सुराज के लिए आवाज बुलंद की। बलिया को कुछ ज्यादा ही दमनचक्र से गुजरना पड़ा। 18 अगस्त को बैरिया, रसड़ा, सुखपुरा आदि स्थानों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी और उसमें नौजवानों और छात्रों के बलिदान से बलिया का खून खौल उठा। तकरीबन दस लाख की आबादी सड़कों पर उतर आई। रेलवे लाइनें उखाड़ ली गईं, थाने और तहसील लूट लिए गए। दिलचस्प यह है कि तब बलिया के कलेक्टर कोई अंग्रेज नहीं, भारतीय जगदीश्वर चन्द्र निगम थे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि निगम को हारकर बलिया जेल में बंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चित्तू पांडेय को छोड़ना पड़ा। 19 अगस्त के दिन बलिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और चित्तू पांडेय उस सरकार के मुखिया बने, जबकि क्रांतिकारी महानन्द मिर पुलिस प्रमुख। इस आजादी के बाद जिस व्यवस्था ने पांच-छह दिन तक व्यवस्था चलाई उसे सुराजी सरकार नाम दिया गया था। बलिया के साथ मिदिनापुर के तामलुक ओर महाराष्ट्र के सतारा में भी ऐसी ही सरकारें बनीं। तीनों जगह पांच से लेकर हफ्ते भर में अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो दमनचक्र चला, सिहरन के बाद उसे याद करने वाली पीढ़ी भी अपनी उम्र पूरी करके दुनिया को विदा कह चुकी है। इसके बावजूद वह दमन बलिया के लोगों के रगों में आज भी दौड़ रहा ह। ब्रिटिश 23 अगस्त की रात में संयुक्त प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर हैलेट ने बनारस के कमिश्नर नेतर सोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी बनाकर बलूच फौज के साथ भेजा। इसी दिन दोपहर में कब्सर की ओर से जल मार्ग से मार्क स्मिथ और 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्वमें ब्रिटिश फौज बलिया पहुंची। और फिर वह बलिया में हिटलर की नाजी सेना बन गई। दमन के आगे निहत्थी जनता कितने दिन तक टिकती।बलिया का सत्ता हस्तांतरण खारिज करके उसपर ब्रिटेन का कब्जा कर लिया गया। हैलेट ने ब्रिटिश भारत के सचिव को अगस्त 42 के आखिर में बलिया पर कब्जे का टेलीग्राम भेजा और बीबीस ने इस पर खबर प्रसारित की।

अगस्त का महीना हमारीआजादी के इतिहास को ही समेटे नहीं है, बल्कि इस महीने के साथ कई क्रांतियों का गौरवमयी इतिहास भी समाहित है। तारीख में उन घटनाओं को तवज्जो तो मिली है लेकिन भावी इतिहास के संदर्भ में उनके प्रभाव को अहमियत नहीं दी गई है। बलिया तामलुक और सतारा की क्रांतियों और वहां स्वाधीन भारत से पहले ही सुराजी या

सानीय सरकार की स्थापनाओं ने भावी इतिहास पर कितना प्रभाव डाला है इस नजरिए से उन्हें नहीं देखा-समझा गया। नौ अगस्त 1942 की सुबह मुंबई में कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे वालंटियर और कार्यकर्ताओं को या तो रास्तों के स्टेशनों पर ही उतार दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले की रात को कांग्रेस भारत छोड़ प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी। संदर्भ के लिए स्मरीणय है कि भारत छोड़ा का नारा कांग्रेस में सक्रिय समाजवादी धड़े के युवा नेता युसुफ मेहर अली ने दिया था। चूं आजकी तरह उन दिनों संचार के माध्यम नहीं थे, लिहाजा गांधी नेहरू पटेल समेत तमाम कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी की खबरें देर से देश के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचीं। जैसे-जैसे ये जानकारी पहुंची इलाकों में अंग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता गया।

यूरोपीय देशों की सभ्यता की इतिहासकार जब भी चर्चा करते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच समाज को सबसे ज्यादा सुसंस्कृत माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश समाज कितना सभ्य था, इसे भारत में किये उसके दमन चक्र से समझा जा सकता है। मजेदार बात यह है कि 42 की क्रांति के दौरान ही दूसरा विश्वयुद्ध जारी था। यूरोप में हिटलर को नाजी बताकर ब्रिटिश सेनाएं उसके विरोध में युद्धरत थीं। तब जर्मन शासक हिटलर यूरोप की नजर में असभ्य था। हिटलर को असभ्य और अमानवीय बताने वाली ब्रिटिश सरकार भारत में उन्हीं दिनों हिटलर जैसा ही कहर ढा रही थी। इतिहास में 42 की क्रांति और अंग्रेजों के दमन को इस नजरिये से भी कभी व्याख्यायित नहीं किया गया।

बलिया की आजादी और हिंसा को लेकर सवाल भी उठाये गये7 जाहिर है कि सवाल उठाने ाले ब्रिटिश सभ्यता पोषक ही थे। लेकिन अ-हंसा के पुजारी गांधी ने उन सवालों को खारिज कर दिया था। उन्होंने बलिया की घटनाओं के ब्रिटिश सरकार के दमन और अत्याचा को ही जिम्मेदार बताया था। अहमदनगर जेल से छूटते ही बलिया को लेकर जवाहर लाल नेहरू ने जो कहा था, वह भी अहम है। उन्होंने कहा था कि उस हालात में वे ऐसा ही करते, जैसा बलियावालों ने किया। इस घटना के दो दशक पहले ही असहयोग आंदोलन के दारान भी बलिया पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार झेलने पड़े थे। गांधी जी को इसकी रिपोर्ट उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी ने भेजी ीी, जिसके आधार पर गुजराती नवजीवन में गांधी जी ने बलिया पर लेख लिखा था। पूरी दुनिया बलिया को अक्खड़ बताती है, लेकिन इस लेख में गांधी जी बलियावालों को सज्जन बताते हैं। 1925 में बलिया पहुंचे जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि वे बलिया की सरजमीं को चूम लेना चाहिते हैं। इस इतिहास को बदलने में इन घटनाओं की अहम भूमिका रही है। इनके चलते आंदोलनकारी इलाकों ने इतिहास ही नहीं बाद के दौर में भी कीमत चुकीं है। यह कीमत कभी पिछड़ापन के रूप में दिखती है तो कभी मूल्यांकन की कमी के रूप में। इतिहास की खासियत यह है कि वह नए संदर्भों में फिर से नए सिरे से उठ खड़ा होता है यह इतिहास उठ रहा है औरअपना हक मांग रहा है।

घूँघट की बगावत

25 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भारत की बांग्लादेश के प्रति प्रतिबद्धता जगजाहिर

फुदान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज की डिप्टी डायरेक्टर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स अखबार से कहा है कि बांग्लादेश में ठोस आर्थिक वजहों से प्रदर्शन शुरू हुए थे। उनका कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।

दक्षिण एशिया के बदलते भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक एवं भू-सामरिक परिदृश्य भारत के लिए बड़ी चिन्ता एवं चुनौती का विषय बनता जा रहा है। बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने लोकतांत्रिक देशों को हिला कर रख दिया है। दक्षिण एशिया के देशों में भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं और अक्सर अफगानिस्तान भी इनमें शामिल होता है, यद्यपि यह मध्य एशिया के भू-भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित दक्षिण एशिया का क्षेत्र विशेष भू-राजनीतिक, भू-सामरिक एवं भू-आर्थिक महत्व रखता है। दक्षिण एशियाई देशों में घटित घटनाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव भारत पर सर्वाधिक पड़ता है। पड़ोसी देशों की अस्थिरता, अराजकता तथा अनिश्चितता का असर भारत पर पहले और प्रभावी रूप से पड़ता है। पड़ोसी देशों में पनपने वाली राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता भारत के लिए एक समस्या और संकट का सबब हो सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में भारत समर्थक शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट होने और उपद्रवी तत्वों द्वारा लूटपाट, हिंसा, हत्या तथा अराजकता का माहौल विशेष रूप से भारत की चिंता को बढ़ा रहा है।

चालाक चीन का कूटनीतिक चक्रव्यूह भी विगत एउक दशक से बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत आधार बनाने के प्रयास में चलाया जा रहा था। शेख हसीना के भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों के कारण उसे उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही थी। वास्तव में चीन अस्थिर पड़ोसियों के माध्यम से भारत के भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक एवं भू-सामरिक परिदृश्य को बदलने के निरंतर प्रयास में जुटा हुआ है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए भारत विरोधी शक्तियां सक्रिय होकर संकट पैदा करने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बेहद मजबूती मिल सकती है, जिससे भारत को बड़ी एवं कड़ी चुनौती का निकट भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में बांग्ला देश में ऐसी स्थिति तथा परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिनके फलस्वरूप वहीं भारत विरोधी भावनाएं चरम पर हैं।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी, दोनों ही शेख हसीना की भारत से निकटता के कारण भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। बांग्लादेश का तख्ता पलट आकस्मिक घटनाक्रम नहीं है। वह वास्तव में पूर्व नियोजित षड्यंत्र का परिणाम है, जिसमें एक ओर अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों द्वारा सत्ता परिवत्रन का परोक्ष खेल खेला गया वहीं चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ ने शेख हसीना सरकार की जड़ों को खोखला करने के लिए लिए आईएसआई एवं चीन मिशन एजुकेशन द्वारा इस अभियान को अंजाम दिया। भारत के साथ बांग्लादेश की मित्रता चीन और पाकिस्तान को किसी तरह पच नहीं रही थी। आईएसआई के सीनियर कमांडर (ऑपरेशन) जावेद मेहं को इसका उत्तर दायित्व दिया गया। इसके द्वारा सबसे पहले बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच गठबंधन कराया गया। इसके बाद ही जमात-ए-इस्लामी के स्टूडेंट विंग को तत्पर तैनात और तैयार रहने का काम किया गया।

चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने लिखा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जलद शांति और स्थिरता बहाल होगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक अग्रलेश में इस बात का उल्लेख किया हे कि छात्रों का आंदोलन केवल राजनीतिक मंशा से प्रेरित नहीं था, बल्कि इसके पीछे मजबूत आर्थिक वजहें भी थीं। शंघाई इंस्टीच्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज की निदेशक लियु जोगई ने ग्लोबल टाइम्स से कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है यहां करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं जिनमें से एक बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी की तलाश है। वह कहती हैं कि महंगाई और आर्थिक समस्याओं ने शायद विरोध को ज्यादा हवा दी। लेकिन सरकारी नौकरी में कोटा व्यवस्था खत्म करने के बावजूद स्थिति सामान्य होने के बजाय ये प्रदर्शन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गए।

फुदान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज की डिप्टी डायरेक्टर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स अखबार से कहा है कि बांग्लादेश में ठोस आथ्रिक वजहों से प्रदर्शन शुरू हुए थे। उनका कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक में कहा है कि भारत ने शेख हसीना को हर संभव मदद देने का वादा किया है। अखबार लिखता है कि भारत की समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एस जयशंकर ने शेख हसीना को भविष्य के लिए फैसला लेने का वक्त दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने शेख हसीना को लेकर भारत की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया है। चीन के कुचक्र ने युवा बांग्लादेशी छात्रों को मोहरा बना कर शतरंजी चाल चलनी शुरू कर दी और शह-मात देने का खेल निरंतर बढ़ता गया। चीन एजूकेशन मिशन के नाम पर बांग्लादेशी छात्रों को छात्रवृत्ति सहित शिक्षा देने का अभियान चलाया। इसके तहत उच्च शिक्षा के संस्थानों सहित मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश का भी बड़ा इंतजाम किया। इनका ब्रेनवॉश इस तरह किया गया कि इन्हीं लोगों ने चीन के स्लीपर सेल बन कर छात्रों केबीच आंदोलन को तेज कर दिया। आईएसआई के माध्यम से बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लाम व स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता भी दी गई। जबां, जोश जुनून से भर कर युवाओं ने होश खोकर अराजकतापूर्ण घटना को अंजाम दिया।

पड़ोसी देशों में घटित घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है। अस्थिर पड़ोसी देश इस समय भारत की चिंता तथा चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार विदेशी कर्ज के बोझ से बढ़ती महंगाई की वजह से बड़े आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, जो कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। चीन की मदद से टिका पाकिस्तान भारत के विरूद्ध आतंकवादी हमले करके संकट पैदा करता रहा है। चीन समर्थक मालदीव भारत के भू-सामरिक एव भू-राजनीतिक हितों को प्रभावित कर रहा है।

हां देर से सही अब भारत के सहयोग के लिए स्वयं अपेक्षित बहुमूल्य साझेदार कह रहा है। जहां तक श्रीलंका का सवाल है तो चीन के कर्ज में जकड़े होने के कारण वह मजबूर होकर भारत विरोधी गतिविधियां अपनाने लगता है। नेपाल में ओली सरकार चीन के आगे झोली फैला लेती है, और कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को मानचित्र में नेपाल का क्षेत्र बताती है। पूर्वी देश म्यांमार में विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन में अपनी सेंध लगा रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का वातावरण बन चुका है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वहां के आतंकी समूह पुनः संगठित होने की फिराक में हैं। बांग्लादेश में अराजकता, अफरातफरी, अनिश्चितता, अस्थिरता, अपराध, आतंक, अत्याचार एवं अंधेरगर्दी का आलम यह है कि विद्रोह के बाद भी वहां का वातावरण अशांत बना हुआ है। अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद युनुस को सत्ता सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता युनुस को शुभकामनाएं दीं और एक्स पर लिखा-हम शीघ्र ही सामान्य स्थिति की वापसी की आशा करते हैं, जिससे हिन्दुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए दोनों देश के लोगों की सझाा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्ला देश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उफनाई सरयू...छह गांवों के रास्ते बंद

धनघटा, संत कबीरनगर (जीकेबी)। सरयू नदी शनिवार को बिडहर घाट पर 79.150 मीटर पर पहुंच गई। खतरे के निशान 79.400 मीटर से महज 25 सेंटीमीटर नीचे भले ही बह रही है लेकिन समीपवर्ती गांवों के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल गया है। छह गावों का संपर्क मार्ग अवरूद्ध हो गया है। बच्चे नाव से विद्यालय जा रहे हैं। लगातार पांच दिनों से सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही। नदी धीरे-धीरे बढ़ते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। समीपवर्ती गांव गायघाट दक्षिणी, आगापुर गुलरिहा, चकदहा, ढोलबजा, कंचनपुर चपरा पूर्वी गांव के चारों तरफ का रास्ता अवरूद्ध होने लगा है। माझा क्षेत्र कि फसलें जहां जलमग्न हो गई हैं वहीं पशुओं के लिए चारा का संकट उत्पन्न होने लगा है। ग्रामीण रामसेवक, तामेश्वर, जटाशंकर, रामपाल, जसई, इस्रावती, कमला आदि ने बताया कि नदी इसी तरह बढ़ी तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों का मकान गांव के बाहर है उनके दरवाजे तक पानी पहुंचने लगा है। बाढ़ के कारण बिजली निगम ने सप्लाई बाधित कर दी है। जिससे टॉर्च के रोशनी में रहना और खाना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण जीव-जंतु का भी भय सताने लगा है। उपरोक्त स्थितियों के विषय में तहसीलदार योगेंद्र पांडेय का कहना है कि - बाढ़ से प्रभावित गांवों का दौरा किया। बताया कि कुछ गांव के रास्ते आंशिक रूप से अवरुद्ध होने लगे हैं। इन गांव में नाव लगा दी गई है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां तत्काल नाव लगाई जाएगी। वैसे उम्मीद है कि रविवार से सरयू नदी का जलस्तर घटने लगेगा।

राप्ती का जलस्तर घटा...कटान की आशंका

मेंहदावल, संतकबीरनगर (जीकेबी)। क्षेत्र में राप्ती नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। वर्तमान समय में लाल निशान से जलस्तर 33 सेमी नीचे आ गया है। शनिवार को नदी का जलस्तर 79.70 मीटर पर आ गया। इससे बाढ़ खंड द्वितीय के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। 19.2 किलोमीटर लंबी तटबंध करमैनी-बेलोली पर राप्ती का जलस्तर अब लगातार घट रहा है। जहां शुक्रवार को राप्ती का जलस्तर शाम 5 बजे 79.30 मीटर पर रुका था। वहीं शनिवार को राप्ती का जलस्तर 79.17 मीटर पर आ गया है। जलस्तर घटने के बाद भी काटन की स्थिति देखी जा रही है जिससे विभागीय स्तर पर निपटने के लिए बाढ़ निरोधक कार्य करने में जुटे हुए हैं। बेलौली में किलोमीटर 16,500 से 17.500 मीटर के बीच हो रहे कटान को रोकने के लिए विभाग ने बोरी तथा अन्य सामग्री डालकर रोका, जबकि बिशनपुर बांगर में अभी नदी का जलस्तर तटबंध से सटकर बह रहा है लेकिन तटबंध सुरक्षित है।

सहायक अभियंता राम उजागिर लाल का कहना है कि जलस्तर लगातार घट रहा है। जलस्तर घटने के बाद भी तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी विभागीय अधिकारी तटबंध पर रहकर जलस्तर तथा बांध की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

मुफ्त यात्रा... की सौगात दुश्वारियों भरी

महराजगंज(जीकेबी)। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त यात्रा की सौगात दुश्वारियों से भरा रहा। पहले तो समय से बस नहीं मिली, अगर आ भी गई तो बैठने के लिए धक्का-मुक्की करनी पड़ी। लोकल रूटों पर महिलाओं को टेंपो-टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। जिम्मेदारों ने रक्षाबंधन पर बेहतर ढंग से मुफ्त यात्रा कराने का दावा किया था, लेकिन ये दावे हकीकत में फेल नजर आई।

सोमवार को महराजगंज शहर के बस स्टेशन पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। दोपहर करीब एक बजे के बाद रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त था। इस वजह से बहनें जल्दी बस स्टेशन पहुंच गईं। यहां कोई घंटे भर परेशान रहा तो कोई डेढ़ घंटे तक इधर-उधर भटकता रहा। दोपहर 12 बजे एक बस आई तो उसमें बैठने की होड़ लग गई। काफी जद्दोजहद के बाद कुछ महिलाओं को बैठने के लिए जगह मिली। इसके पीछे दूसरी बस भी आई, उसमें भी बैठने के लिए धक्का-मुक्की करनी पड़ी। गोरखपुर रूट पर जाने के लिए थोड़ी कम परेशानी हुई, लेकिन ठूठीबारी रूट पर अधिक समस्या हुई। सिसवा जाने के लिए ज्ञानती देवी स्टेशन पर आईं तो उनको पता चला की कोई बस नहीं है। वह आगे बढ़ीं और टेंपो से सवार होकर चली गईं। इसी तरह चौक बाजार आने के लिए शांति देवी परेशान दिखीं। वह आसपास के दुकानदारों से पूछ रही थीं। इस तरह से स्टेशन परिसर में महिलाएं गंतव्य तक जाने के लिए परेशान दिखीं। बसें स्टेशन पर आई तो उसमें बैठने के लिए होड़ लगी रही। एक बजे के पहले तक यह समस्या बनी रही।

सरकार और समाज मिलकर करें कट्टरपंथियों का सामना

ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कट्टरपंथ का उभार कोई आज की बात है। इसका तात्कालिक राजनीतिक जन्म शेख हसीना के धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के अपनाने के बाद काफी हुआ। बांग्लादेश, जिसने अपने जन्म के साथ ही धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता को अपनाने का प्रयास किया, आज गहरे संकट का सामना कर रहा है। शेख हसीना के नेतृत्व में आवमी लीग ने बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए लेकिन हाल के वर्षों में इस्लामिक उग्रवाद और धार्मिक कट्टरपंथियों का उभार इस दिशा को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामी उग्रवाद का प्रभाव कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट और इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता के खात्मे की कोशिशें, इस लेख के मुख्य विषय हैं।

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने बांगलादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार उद्योग रहा है, जो देश की जीडीपी का 15 प्रतिशत और कुल निर्यात का 80 प्रतिशत हिस्सा बनाता है। महामारी के कारण वैश्विक बाजार में मांग में भारी गिरावट आई, जिससे कई कारखाने बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बांगलादेश की अर्थव्यवस्था, जो शेख हसीना के नेतृत्व में पहले बढ़ रही थी, अचानक ठहराव की स्थिति में आ गई। 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी विकास दर 7.9 प्रतिशत थी, लेकिन 2020 में घटकर 3.4 प्रतिशत और 2024 में 5.8 प्रतिशत हो गई। इस दौरान गरीबी दर में भी मामूली वृद्धि हुई। जिससे समाज में आर्थिक असंतोष और अविश्वास का माहौल बना। महामारी के बाद की स्थिति में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष ने इस्लामी कट्टरपंथियों को अपनी विचारधारा फैलाने का मौका दिया। इसलामी कट्टरपंथियों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। आर्थिक संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और शेख हसीना की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ बताया। इस दौरान, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों में भी वृद्धि देखी गई, जो इस्लामी कट्टरपंथियों के उभार का एक और प्रमाण था।

चार जून 2024 को बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली का आदेश दिया जिसने मुक्ति-योद्धाओं के वंशजों के लिए 30 नौकरियां आरक्षित की गईं। इस निर्णय ने छात्रों के बीच गहरे असंतोष को पैदा किया और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों का यह विरोध जो शुरू में कोटा प्रणाली के खिलाफ था। धीरे-धीरे सरकार विरोधी और इस्लामी कट्टरपंथियों के समर्थन में बदल गया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए सरकार के धर्मनिरपेक्ष एजेंडे का विरोध किया और शेख हसीना को सत्ता से हटाने का दबाव बनाया।

भारत विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल बनाने के अंग्रेजी फरमान ने समाज में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों केबीच में लंबी खाई खींची जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में समय-समय पर राजनीतिक खींचतान चलती रही। 1971 के पाकिस्तान से अलग होने के बाद से ही बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी के रूप में बहुसंख्यक समाज का जन्म हुआ। जिसको लम्बे समय तक राजनीतिक लाभ तो मिला लेकिन समाज के अल्पसंख्यक समुदाय धीरे-धीरे हाशिये पर चले गए।

बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो चली। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक अस्थिरता पर राजनीतिक समझ रखने वालों की तरफ से विभिन्न विमर्शों का दौर जारी है, जिनमें वहां की जनता का तत्कालीन सरकार से मोहभंग सबसे प्रमुख है। बांग्लादेश में राजनीतिक आग की शुरुआत कोई नई बात नहीं है। भारत विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल बनाने के अंग्रेजी फरमान ने समाज में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों केबीच में लंबी खाई खींची जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में समय-समय पर राजनीतिक खींचतान चलती रही। 1971 के पाकिस्तान से अलग होने के बाद से ही बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी के रूप में बहुसंख्यक समाज का जन्म हुआ। जिसको लम्बे समय तक राजनीतिक लाभ तो मिला लेकिन समाज के अल्पसंख्यक समुदाय धीरे-धीरे हाशिये पर चले गए।

शेख हसीना की धर्म निरपेक्ष नीतियों ने बांग्लादेश को आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास ने इस्लामी कट्टर पंथियों को भी उभरने का अवसर दिया। हसीना के विरोधियों ने धर्मनिरपेक्षता को इस्लामी परम्पराओं के खिलाफ बताया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक असंतोष का लाभ उठाते हुए हसीना सरकारके खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू किया। उनकी रणनीति में धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सामाजिक असंतोष को बढ़ाना और हसीना की धर्म निरपेक्ष नीतियों का विरोध करना शामिल था। इस्लामी कट्टरपंथियों ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी देश को प्रभावित किया। अल्पसंख्यकों पर हमला किए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया और धाार्मिक सहिष्णुता को चुनौती दी।

हराधेन रॉय और उनके भतीजे की हत्या जैसी घटनाएं इस बात के प्रमाण हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों का संतोष राजनीतिक नहीं धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। शेख हसीना की सरकार ने कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बांग्लादेश में मजबूत विरोधी शक्ति के रूप में उभरने में सफल रहे। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार किया और देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक समर्थ न प्राप्त किया।

बांग्लादेश में धर्म निरपेक्षता और इस्लामी कट्टरपंथ के बीच संघर्ष ने देश के भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। शेख हसीना के नेतृत्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों के उभार ने इन प्रयासों को कमजोर किया। देश के राजनीति ढांचे में अस्थिरता, आर्थिक संकट और धाम्रिक असंतोष ने बांग्लादेश के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि देश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखा जाए ताकि बांग्लादेश को स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में बढ़ाया जा सके। इस्लामी कट्टरपंथियों के उभार ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। हसीना ने देश को आधुनिक और धर्म निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास के परिणामस्वरूप उनका तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के भविष्य के लिए आवश्यक है कि धर्म निरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दल एक जुट हों। देश को स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करें और इस्लामी कट्टरपंथ के खतरों का सामना करें।

हरी बत्ती

सुंदर नयन, मोरनी सी चाल ,गोरा रंग ये सब देखकर मैं अचंभित हो गया कि इतनी सुन्दर लड़की यहां सड़क किनारे भीख मांग रही है। मैं उत्सुकता से उसकी तरफ देखे जा रहा था ।इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता बत्ती हरी हो गई और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली ।गाड़ी तो मैंने आगे बढ़ा ली थी परंतु पीछे बहुत सारे सवालों को छोड़कर आ गया था ।

मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे कितनी सुंदर देखने में भी अच्छे घर से लग रही है।

फिर सड़क पर भी क्यों भीख मांग रही है? मन में लाखों सवालों को लिए मैं अपनी मंजिल जानी की अपने दफ्तर आ गया ।दिन भर मैंने काम तो किया परंतु मेरा धान सिर्फ उसी सुंदर स्त्री की तरफ रहा। जब मैं वापिस आ रहा था तो जैसे ही बत्ती आई मैं सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रहा था। कहीं से वो सुंदर लड़की मुझे फिर मिली मैंने उसे बुलाया बेचारी दौड़ी चली आई, मैं उसकी तरफ देखी जा रहा था परंतु आगे से उसे लड़की ने कहा साहब क्या देख रहे हो पैसे देने हैं तो दो वरना मैं आगे जाऊं। मैंने कहा नहीं नहीं देता हूं जेब से ₹100 निकाले और उसके हाथ में देते हुए उसे पूछने लगा आप यहां कब से हैं ।अरे साहब आपको क्या लेना इन सब बातों से अपना काम करें इतनी देर में पीछे गाड़ी वालों ने हॉरन बजा बजा इतना शोर कर दिया मैंने आनन फानन में गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी।

मन सवालों को लिए मैं घर पर आ गया। खाना खाया थोड़ी देर आराम किया और फिर सो गया । मुझे पता ही नहीं लगा मैंने कब खाना खाया कब मैं सोचते सो गया ।परंतु सोते-सोते भी मन में वही सवाल दौड़ रहे थे। अगले दिन सुबह बत्ती पर मुझे फिर से वही सुंदर लड़की मिली ।मैंने उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया वह भी दौड़ी आई मैंने उनसे पूछा आप यहां पर भी कितने दिनों से भीख मांग रही हो। वह जोर-जोर से हंसने लगी मैंने उसे दोबारा फिर पूछा फिर भी वह जोर-जोर से हंसने लगी, फिर उसने कहा साहब पैसे देने हैं तो दीजिए वरना कोई सवाल मत पूछिए। इतनी देर में फिर बत्ती हरी हो गई और मैंने गाड़ी को रफ्तार दी पर सवाल वही के वही थे ।पता नहीं कैसे उसके बारे में जाने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी ।पता नहीं क्यों मुझे दिन भर की दिनचर्या के बाद मुझे बस एक ही बात का इंतजार रहता है कि कब दफ्तर की छुट्टी होगी और मैं उस अनजान लड़की से मिलूंगा ऐसा करते-करते रविवार आ गया और आज मुझे ऑफिस तो नहीं जाना था। तो इसलिए मैंने उस सुंदर स्त्री से मिलना का मन बनाया ।

मैंनें सोचा क्यों ने आज उससे ही मिला जाए ।मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा उस बत्ती की तरफ और जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ वह सुंदर स्त्री इस बत्ती पर लोगों से पैसे मांग रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उसे अपने पास बुलाया और उसे फिर पूछा परंतु उसने बताने से सब कुछ मना कर दिया फिर मैंने उसे दोबारा फिर पूछा उसने कहा साहब कक्या बात है मैं देख रही हूं आप दो तीन दिन से मुझे बुला कर पैसे देते हो आपके दिमाग में क्या चल रहा ।अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं सिर्फ आपके बार में जानना चाहता हूं।

ठीक है साहब बताती हूं पर उसके बाद आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। मैं हड़बड़ा कर बोला हां हां नहीं पूछूंगा।

उसने जो मुझे बताया सुन कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए ।

उसने मुझे बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी उसके साथ भाग कर शहर में आ गई। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद लड़का मुझे इसी लाइट पर छोड़कर भाग गया और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी । मैं किसी को जानती भी नहीं थी इसलिए मैंने इसी लाइट के झूग्गी में रह रही एक काकी से मिली उसने मुझे अपने पास रख लिया ।बदले में उसके लिए खाना बना देती हूं ।जब साहिल ने मुझे छोड़ा तब मैं प्रेग्नेंट थीं।

मैनें सोचा इस नन्ही जान का क्या कसूर है इसलिए मैंने इसको इस, दुनिया में लाने की ठानी।

काकी को बताया तो उसने कहा मैं तेरे को तो खिला सकती है पर दो दो को नहीं।- इसके लिए तुझे कमाना पड़ेगा मेरे पास कोई घर तो नहीं है ना इतने पैसे हैं कि मैं कहीं पर रह लूं इसलिए मैं इसी लाइट पर पैसे मांगती हूं और अपने बच्चे का पेट भरती हूं।और मुझे बातों बातों में पता लगा कि वह पढ़ी-लिखी लड़की गांव वापस इसलिए नहीं जा रही थी कि गांव में जाकर दोबारा माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी ।उसने बताया साहब मेरा एक खराब फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी।

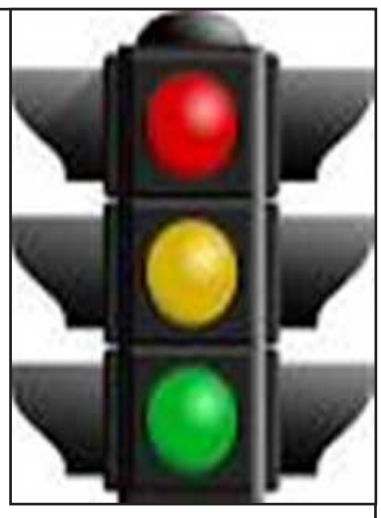

जिंदगी में कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। हमें जीवन में माँ बाप की बात माननी चाहिए,जो नहीं मानते उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। मेंने लाख कोशिश की गाँव का नाम पूछने की पर गौरी ने सिर्फ अपना नाम बताया और कुछ नहीं। फिर मेंने उसे कुछ पैसे दिए और मेरी तरफ देखती रही और कहा साहब बहुत दिनों बाद इतने पैसे देखें है और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया परंतु फिर भी मैं लाख सवाल अपने साथ ले आया।

सीमा रंगा इन्द्रा दिल्ली

आधुनिकता की भट्टी में नैतिकता जल गयी

बढ़ते जा रहे आज क्यों झगड़े झमेले
रहना चाहते हैं क्यों सब अकेले
मेल मिलाप क्यों छूट रहा अपना
भूल गए अब अपने त्योहार और मेले
न किसी से मिलना न बैठ कर बात करना
छोटी छोटी बातों पर
बिना मतलब के लड़ना
क्या हो रहा है यह
सब अपनी नजर के सामने
अमर समझ रहे सभी
याद नहीं किसी को मरना
सब पीछे छूट गए हम आगे बढ़ गए
जिन्दगी की सीढियों पर
कुछ फिसल गए कुछ चढ़ गए
क्या खोया क्या पाया हमने वक्त के साथ
जाति और मजहब के नाम पर लड़ गए
सहनशीलता न जाने कहाँ खो गई
संवेदनहीनता हम पर हावी हो गई
गलत को गलत
कहने की हिम्मत नहीं हमारी
नफरत के बीज हम सबमें बो गई
वक्त बदला हमारी सोच भी बदल गई
वक्त के साथ ही संस्कारों की बलि चढ़ गई
पढ़ाई तो बहुत कर ली जमाने में लोगों ने
लेकिन आधुनिकता की
भट्टी में नैतिकता जल गई

रवींद्र कुमार शर्मा
जिला बिलासपुर
हि प्र

रवि कुमार हुए 'डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित

अमेरिकन ईस्ट कॉस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा 11 अगस्त को मुंबई में आयोजित एक विशाल समारोह के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय व उल्लेखनीय कार्य करने वाले रवि कुमार प्रबंधक ओ.के. मॉडल स्कूल मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली को 'डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया ।अपने पाठकों को बता दें कि छोटी सी उम्र में रवि कुमार ने जिस तरह से शिक्षा व समाजसेवा के क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बनाई है, वह सच में काबिलेतारीफ है। कोरोना काल में जिस तरह रवि कुमार ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व उनके पैरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए उनकी हर संभव सहायता की थी और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए लोगों के लिए काम किया उससे उनकी शख्सियत में चार चाँद लग गए।

रवि कुमार को हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएँ देते हुए यही कहना चाहता है कि आप जिस तरह से शिक्षा व समाजसेवा के क्षेत्र में अपनी उच्चकोटि की सेवाएँ दे रहे हैं। समाज सेवा के साथ साथ रवि कुमार की साहित्य में बेहद रूची है ।वे आए दिन अपने स्कूल में कवि सम्मेलन करवाते रहते है और कवियों को सम्मानित करते रहते हैं ।उनके स्कूल के हर प्रोग्राम में कवियों को समाजसेवा करने वालों अवश्य बुलाया जाता है।

नीरज कुमार सिंह की रचना रक्षाबंधन का उपहार कहानी पर बनी शॉर्ट फिल्म उपहार रक्षा बंधन का नाम से शॉर्टफिल्म का निर्माण (एम .एस.मीडिया)की सौजन्य से हुआ है। विशेष सहयोग महेश शर्मा एम एस मीडिया ओनर का रहा है। इस शॉर्टफिल्म के निर्देशन का कार्य मुकेश विद्यार्थी जी द्वारा किया है। शॉर्टफिल्म में काम करने वाले पात्रों की कास्टिंग काफी सही ढंग से किया गया है, कहानी के पात्र कथा अनुरूप सभी संतोषजनक हैं ।सभी के कार्य सराहनीय है। गौरवतलब बात ये हैं,... की फिल्म उपहार रक्षा बंधन का को रियल्टी चैनल रक्षा बंधन वाले दिन रिलीज किया गया कुछ ही घंटो में शॉटफिल्म हजार के करीब दर्शकों के दिल में जगह बना ली है । इस शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले कलाकार और टेक्निकल टीम के नाम इस प्रकार हैं.. राजाराम जी, चंद्रेश,संजना , बलवंत, रेखा जी,राज गुप्ता आदि ने अपने अभिनय से फिल्म को जीवंत कर दिया है। फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकार गोरखपुर के आर्टिस्ट हैं। फिल्म की कहानी के लेखक ₹नीरज कुमार सिंह , उत्तर प्रदेश ,देवरिया, जिले के ग्राम (घटैला गाजी) से हैं।

दर्शक इस शॉर्ट फिल्म को यू ट्यूब चैनल (रियल्टी) पर देख सकते हैं।

नटवर नागर,राधा रमन,

पल पल जपे नाम ये मन
यशोदा के लाडले,
नन्द के राजदुलारे दुलारे है
गोकुल मे धूम मचाते
ब्रजवासी के प्राण प्यारे है
नटखट कान्हा पर रिझता रहे सदा मेरा मन
नटवर नागर,राधा रमन,
पल पल जपे नाम ये मन
राधा की प्राण प्रिय, रुखमणी की वो गिरधारी है
मीरा की गीतों मे बसी, यही वो कुन्ज बिहारी है
जिस पर न्योछावर क्यों ना हो, मेरा सारा जीवन
नटवर नागर राधा रमन,
पलपल जपे नाम ये मन
धरा की जगजननी को, वात्सल्य का अनुठा भेंट दिया
कर्म ही प्रधान है जगत में, ये नवीनतम उपदेश दिया
ऐसे रचनाकार को मेरा, सादर नमन
नटवर नागर, राधा रमन,
पलपल जपे नाम ये मन
कुरुक्षेत्र मे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया
जीवन को कैसे जीना,पे अनुपम सन्देश दिया
इन आदर्श पर ही चलता रहे सदा ये जीवन
नटवर नागर,राधा रमन,पलपल जपे नाम ये मन
आओ मनाये खुशी उसके अवतरण की याद मे
जीवन बीतता रहे,सदा उस प्रभु की फरियाद मे
जीवन भर नाम तेरा जपता रहे मेरा मन
नटवर नागर राधा रमन,
पलपल जपे नाम ये मन

प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी धमतरी छ ग

समझिये धागों से बंधे 'रक्षा बंधन' के मायने

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे ऊपर है। हो भी न क्यों, भाई-बहन दुनिया के सच्चे मित्र और एक-दूसरे के मार्गदर्शक होते है। जब बहन शादी करके ससुराल चली जाती है और भाई नौकरी के लिए घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है तब महसूस होता है कि भाई-बहन का ये सर्वोत्तम रिश्ता कितना अनमोल है। सरहद पर खड़ा एक सैनिक भाई अपनी बहन को कितना याद करता है और बहनों की ऐसे वक़्त क्या दशा होती है इसके लिए शब्द नहीं है। रंग-बिरंगे धागे से बंधा ये पवित्र बंधन सदियों पहले से हमारी संस्कृति से बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हैं। यह पर्व उस अनमोल प्रेम का, भावनाओं का बंधन है जो भाई को सिर्फ अपनी बहन की नहीं बल्कि दुनिया की हर लड़की की रक्षा करने हेतु वचनबद्ध करता है। भाई-बहन के आपसी अपनत्व, स्नेह और कर्तव्य बंधन से जुड़ा त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में नवीन ऊर्जा और मजबूती का प्रवाह करता है। बहनें इस दिन बहुत ही उत्साह के साथ अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए आतुर रहती हैं। जहां यह त्योहार बहन के लिए भाई के प्रति स्नेह को दशार्ता है तो वहीं यह भाई को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहने भगवान से अपने भाईयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बाँधती हैं परन्तु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित सम्बंधियों (जैसे पुत्री द्वारा पिता को) भी बाँधी जाती है। वास्तव में ये त्योहार से रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसी की भी रक्षा करने को प्रतिबद्ध करता है। अगर इस पवित्र दिन अपनी बहन के साथ दुनिया की हर लड़की की रक्षा का वचन लिया जाए तो सही मायनों में इस त्योहार का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। इस पावन त्योहार का अपना एक अलग स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन बदलते समय के साथ बाकी रिश्तों की तरह इसमें भी बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे-जैसे आधुनिकता हमारे मूल्यों और रिश्तों पर हावी होती जा रही है। संस्कृति में पतन के फलस्वरूप रिश्तों में मजबूती और प्रेम की जगह दिखावे ने ले ली है। आज के बदलते समय में इस त्योहार पर भी आधुनिकता हावी होने लगी है, तब से आज तक यह परंपरा तो चली आ रही है लेकिन कहीं न कहीं हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। रंग-बिरंगे धागों में अब अपनत्व की भावना और प्रेम की गर्माहट कम होने लगी है। एक समय में जिस तरह के उसूल और संवेदना राखी को लेकर थी शायद अब उनमें अब रुपयों के नाम की दीमक लगने लगी है फलस्वरूप रिश्तों में प्रेम की जगह पैसे लेने लगे हैं। ऐसे में संस्कृति और मूल्यों को बचाने के लिए आज बहुत जरूरत है दायित्वों से बंधी राखी का सम्मान करने की। क्योंकि राखी का ये अनमोल रिश्ता महज कच्चे धागों की परंपरा भर नहीं है। लेन-देन की परंपरा में प्यार का कोई मूल्य भी नहीं है। बल्कि जहां लेन-देन की परंपरा होती है वहां प्यार तो टिक ही नहीं सकता, अटूट रिश्तें कैसे बन पाएंगे। इतिहास मे कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमे युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी मे से एक टुकड़ा बाँध दिया था, और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट मे द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। रक्षा बंधन की कथाएं बताती हैं कि पहले खतरों के बीच फंसी बहन का साया जब भी भाई को पुकारता था, तो दुनिया की हर ताकत से लड़ कर भी भाई उसे सुरक्षा देने दौड़ पड़ता था और उसकी राखी का मान रखता था।

प्रियंका सौरभ

लेखक छगनलाल गर्ग की कृति बस यूँ ही निबंध संग्रह का विमोचन सम्पन्न

आबूरोड। राजस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक छगनलाल गर्ग की पुस्तक ₹बस यूँ ही ₹ निबंध संग्रह का विमोचन समारोह पेंशनर समाज , आबूरोड (राजस्थान)के सभागार में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह में अध्यक्ष,पेंशनर समाज, आबूरोड व शहर के उपस्थित प्रबुद्धजन, साहित्यकार, पेंशनर समाज की कार्यकारिणी के पदाधिकारी व समस्त उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ जिसकी शुभकामनाएं आदरणीय राजेश शर्मा जी, उपाध्यक्ष साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली द्वारा लिखी गयी है। इस समारोह में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित रहे ! गर्ग को इस कृति के विमोचन पर साहित्य संगम संस्थान के पदाधिकारियों व रचनाकारों ने बधाई दी है।

घूँघट की बगावत

25 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

8

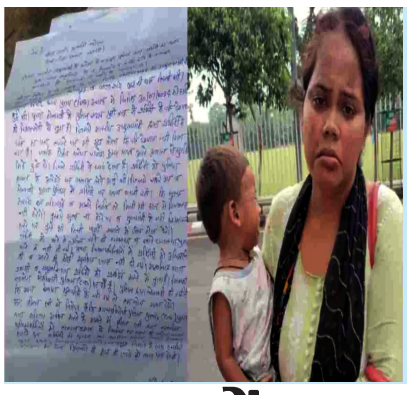

जनता दरबार की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसका तो सीधा अर्थ यही निकलता है कि जिलों में अधिकारी मामले को सनते नहीं हैं जिसके कारण दुखियारों को अपना रूपया पैसा खर्च करके लम्बी लाइन लगाकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना पड़ता है कि शायद यहीं सुनवाई हो जाए।

कागज में बहुत कुछ, हकीकत में कुछ भी नहीं

जनता दरबार की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसका तो सीधा अर्थ यही निकलता है कि जिलों में अधिकारी मामले को सनते नहीं हैं जिसके कारण दुखियारों को अपना रूपया पैसा खर्च करके लम्बी लाइन लगाकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना पड़ता है कि शायद यहीं सुनवाई हो जाए। घटना के बाद पुलिस जितनी सक्रिय हुर्ड।

यदि वह पहले सक्रिय हो जाती तो एक महिला को जिंदा जलने से बचाया जा सकता था। एक छोटे बच्चे को अनाथ होने से बचाया जा सकता था। आखिर उस बच्चे का क्या दोष था जो अपनी मां को जलता हुआ देख रहा था बिना यह जाने हुए कि हो क्या रहा है?

उन्नाव में महिला उत्पीडन की इतनी घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रकृति भी बहुत गम्भीर होती है। उन्नाव कांड के रूप में चर्चित घटना भी तभी प्रकाश में आ पाई थी जब पीड़िता आत्मदाह करने मुख्यमंत्री कार्यालय या आवास तक पहुंच गई थी। उसके बाद आरोपी रहे भाजपा विधायक ने स्वयं प्रदर्शन करके डीजीपी कार्यालय तक जाने की हिम्मत जुटा ली थी। ऐसी स्थिति में जब सीबीआई ने मामले को देखना शुरू किया तब मामला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई हुई। यह स्थिति है कारंवाइयों की। पीड़िता के चाचा की जेल में ही मौत हो गई और उसका इलाज तक नहीं होने दिया गया। जब जिलों में ऐसी स्थितियां होती हैं तभी लोग जिलों से भागकर राजधानी में न्याय मांगने आते हैं? उन्नाव में जिलाधिकारी भी हैं।

पुलिस अधीक्षक भी, भाजपा के सांसद भी हैं विधायक भी। फिर भी जिस प्रकार महिला को जिले से भागकर जनता दरबार में अपने मामले की ओर ध्यान दिलाने के लिए आत्मदाह तक करने की जरूरत पड़ गई उससे यही लगता है कि हमारा शासन प्रशासन कितना संवेदनहीन हो चुका है। वे रोबोट हो चुके हैं। वे इन्सान नहीं

रह गाए हैं। इस मामले में उकसावे के लिए चाहे वकील को सजा हो जाये पेट्रोल बेचने वाले या उसे रिक्शे पर लाने वाले की। लेकिन पुलिस को पहले अपनी गिरेबां में झांकना चाहिए कि वह क्या कर रही थी और इतने सूरक्षित इलाके में महिला ने आग कैसे लगा ली ? वहीं व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं कि ऐसी स्थितियों के लिए कागज में बहुत कुछ है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है।

उन्नाव की एक महिला जो घर से अपने छोटे दुधमह बच्चे के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार के लिए आई थी। अपने बच्चे को सड़क पर बैठाकर अपने बैग से पेट्रोल भरी बोतल अपने ऊपर डालकर आग लगा ली थी। आग लगाने के बाद पुलिस वाले दौड़े तो लेकिन वह भी खाली हाथ कछ करने की स्थिति में नहीं रहे जब तक वे कुछ करते महिला अपने बच्चे को निहारती हुई 90 फीसद तक जल चुकी थी। उसके बैग में उसका प्रार्थना पत्र था, एक मोबाइल थी। इन सब चीजों से अनजान वह बच्चा अपनी मां को निहार रहा था और मां बच्चे को निहारते हुए आत्मदाह कर चुकी थी। तुर्त-फुरत में उसे अस्पताल पहंचाया गया जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। वह 90 फीसदी से अधिक जल चुकी थी और उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। महिला ससुराल परिवार से पीडित थी। जब वह अपने बच्चे को लेकर ससुराल पहुंची तो लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। मजबूरन वह बच्चा लेकर शिकायत करने थाने गई वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई और जब वह परेशान हो गई तो उसके पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा प्रतिरोध में कोई रास्ता नहीं बचा। घर परिवार के विवादों में किसी महिला को इस सीमा तक जाना पड़े यह आसान नहीं है। बहुत तकलीफ में ही ऐसा कदम कोई उठा सकता है और वह भी ऐसे समय में जब वह अपने घर से इतनी दूर मुख्यमंत्री अवास के पास पहुंचकर इस घटना को अन्जाम दे यानी तब तक उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव न हो।

इस घटना के लिए पुलिस ने जहां एक वकील को पकड़कर जेल में डाल दिया है वहीं पेट्रोल देने वाले और ई-रिक्शा जिससे वह पेट्रोल लेने गई थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। लेकिन पुलिस उस महिला को वहां नहीं बचा सकी जहां इतने पुलिस कर्मी रहते हैं और वह भी मुख्यमंत्री आवास के पास। मुख्यमंत्री आवास के पास जहां इतनी सुरक्षा होती है कि सामान्य दिनों में कोई बिना अनुमति के उस सड़क पर नहीं जा सकता है। यदि कोई जाने की जबरन कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। उसके बैग में वह प्रार्थना पत्र खून के आंसू रो रहा था जिसमें वह कार्रवाई की मांग को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पर गई थी।

थानों का क्या हाल है। यह तो किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक थाने में महिला पुलिस की नियुक्ति है फिर भी ऐसे मामलों में कोई सुनवाई ही नहीं होती है। पुलिस पारिवारिक विवाद में यदि कोई कार्रवाई भले ही न करती घरेलू हिंसा के तहत वह उसे घर में जगह तो दिला ही सकती थी। यदि वह यह भी नहीं कर सकती थी तो कम से कम वह उसकी सुन कर उसे दिलासा तो दे सकती थी। किसी महिला संगठन को मामला सौप सकती थी।

परिवार परामर्श केन्द्र के लिए उसे भेज सकती थी तो उसकी जान तो बच जाती। ऐसे में वह महिला कहां जाती जहाँ मायके से यही बताया जाता हो कि शादी कर दी है ऐसे में तो उस घर से अर्थी ही आएगी। कानूनों में बदलाव के बावजूद मायके में इन महिलाओं के हिस्से में कुछ भी सम्पत्ति नहीं होती है जिसके कारण वे न तो यहां की रह जाती हैं और ससुराल के न चाहने पर न वे वहां रह सकती हैं। जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने किसी वकील से अपनी व्यथा सुनाई और जैसा कि होता आया है आमतौर पर यहीं माना जाता है कि कोई सुनने वाला नहीं है तो वकील ने भी कह दिया होग कि सुनवाई तभी होगी जब मुख्यमंत्री के यहां से इस पर ध्यान जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू

यदि वास्तविक हिंसा नहीं तो एक-दूसरे के बारे में हम हिंसक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसे कैसे रोका जाए? यदि डॉक्टर के साथ हिंसा जारी रही तो फिर रोगियों का क्या होगा। कोलकता की घटना के पीछे क्या तथ्य हैं यह पता नहीं लगा है। परंतु जो समाज को संचालित करते हैं और जिनका समाज पर दबदबा रहना चाहिए यदि वे ही ऐसी स्थिति में आ जाएं कि वे असामाजिक तत्वों से डरें और अपना कर्तव्य निर्वहन न कर पाएं तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। ब्रिटेन में पुलिस का इतना दबदबा है कि साधारणतः असामाजिक तत्व अपना सिर नहीं उठा पाते हैं। अमरीका में भी असामाजिक तत्वों को भी डर कर रहना पड़ता है। वहां न्याय की प्रक्रिया अत्यधिक द्रुत गति से चलती है। अभी कुछ दिन पहले वहां के एक काले नागरिक को गोरे पुलिस वाले ने मार डाला था। द्रुत गति से तय हुआ और उसे आवश्यक सजा दी गई। हमारे देश में तो बरसों लग जाते हैं एक अपराधी को दंडित करने में। सुरक्षा अकेली डॉक्टरों की नहीं पूरे समाज की आवश्यक है। यह कैसे संभव हो इस पर पूरे देश को विचार करना आवश्यक है। वैसे जहां तक डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल है आम लोगों में डॉक्टरों की प्रतिष्ठा में काफी कमी आई है। आम लोगों का चिंतन है कि डॉक्टर साधारणतः उनसे ज्यादा वसूली करते हैं। फिर कई किस्म की जाँचों को करवाना भी आवश्यक बता देते हैं। इनमें खून की जांच, एक्स-रे और भी अनेक किस्म की जांचे शामिल हैं। इनमें भी डाक्टरों का प्रतिशत तय रहता है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। यह अत्यधिक दुखद घटना है। इसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ यह पहली घटना नहीं है। डॉक्टर अब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनाए। यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि पूरे देश में इस समय असुरक्षा की भावना है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो अपने को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हो। यहां तक कि वे भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिन पर दूसरों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि लोगों में अब कानून का भय खत्म हो गया है। अब तो आए दिन यह खबरे मिलती हैं कि रेत खनन माफिया ने बड़े अधिकारी पर हमला किया। जब उसने उनके विरूद्ध चोरी कर रेत ले जाने का अपराध कायम किया। अभी तक कई बड़े-बड़े अधिकारी खनन माफिया के शिकार हो चुके हैं। अनेक कॉलेजों में और स्कूलों में आए दिन शिक्षकों पर हमले होते हैं। कुछ दिन पहले उज्जैन में सरेआम एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। अभी हाल में भोपाल के एक कॉलेजों के संचालक पर दिन-दहाड़े हमला कर दिया गया। हमला करने वाले सत्तारूढ़ दल का संगठन विद्यार्थी परिषद से संबंधित थे। रेलवे में यदि टीआई टिकट का पूछता है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। अतिक्रमण कर अनेक लोग मकान बना लेते हैं। जब अधिकारी उनको हटाने जाते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। बिजली का बिल नहीं देने पर बिजली बोर्ड के अधिकारी उस क्षेत्र की बिजली काटने जाते हैं तो उन्हें मारकर भगा दिया जाता है। बैंक का कर्ज वसूल करने के लिए यदि टीम जाती है तो उसे मोहल्ले में प्रवेश नहीं दिया जाता है। महिलाओं के साथ आए-दिन दुष्कर्म हो रहे हैं। जब अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है और प्रभावशाली व्यक्ति उस अपराधी की रक्षा में खड़े हो जाते हैं। बाबूलाल गौर चुनाव लड़ रहे थे उनके खिलाफ भोपाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिसारिया चुनाव मैदान में थे। वे मतदाताओं से संपर्क के दौरान एक वरिष्ठ मतदाता के पास पहुंचे और उनसे वोट देने का अनुरोध किया तो उस मतदाता ने कहा कि मेरा वोट आपको उसी समय मिलेगा जब आप मुझे 200 रुपए देंगे।

बहनों ने बांधा भाई की कलाई पर प्यार लिया रक्षा का वचन

पडरौना(जीकेबी)। रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार को शहर से लेकर देहात तक धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी उन्हें उपहार के साथ उनकी रक्षा का वचन दिया। कहीं बहनों ने मायके जाकर भाइयों को राखी बांधी, तो कहीं भाइयों ने बहनों के घर जाकर राखी बंधवाई। रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत ढंग से मनाया गया। बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी। साथ ही बहनों ने मुंह मीठा कराकर रक्षा का वचन लिया। वहीं, भाइयों ने भी रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार दिए। इस बार रेशम की राखियों के अलावा रुद्राक्ष और बच्चों के लिए कार्टून सहित कई प्रकार की राखियां बाजार में उपलब्ध थीं। इसके अलावा कुछ बहनों ने चांदी से बनीं राखियां भी भाइयों की कलाई पर बांधी। मिठाइयों की दुकानों पर भी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और आकर्षक ढंग में बनीं मिठाइयां उपलब्ध थीं। लोगों ने जमकर राखियों और मिठाइयों की खरीदारी की। तमकुहीरोड प्रतिनिधि के अनुसार सेवरही क्षेत्र में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सेवरही कस्बा के अलावा राजपुर बगहा, रानीगंज, तिवारी पट्टी, टिकुलिया, परसा उर्फ सिरिसिया, जंगलीपट्टी, दोमाठ, पिरोजहा, पिपराघाट, दौनहा, सुमही संतपट्टी, जगदीशपुर, राजपुर खाश, मिश्रौली, ब्रह्मपुर, जोगनी, जवही दयाल, बभनौली, पकड़ीयार, गौरी नगर, मेहदीया, पिपरा मुस्तकिल, अगरवा समेत सभी गांवों में रक्षाबंधन का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया।

स्वयंसेवकों ने मनाया रक्षाबंधन

तमकुहीरोड। सेवरही कस्बे के जायसवाल धर्मशाला परिसर में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया। रक्षाबंधन की परंपरा पर विस्तार से चर्चा की गई। बौद्धिक प्रमुख सुरेश ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इसके बाद ओम शांति संस्था की रिंकी दीदी ने स्वयंसेवकों ने राखी बांधी। इस दौरान नगर कार्यवाह गुरुशरण जायसवाल, सह कार्यवाह राजेंद्र वर्मा, राजेश जायसवाल, निर्मल अग्रवाल, प्रहलाद वर्मा, अरविंद्र जायसवाल, सहदेव बरनवाल, केदार प्रजापति, राजेश्वर गुप्ता, सुनील वर्मा, प्रदीप वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

चेयरमैन के प्रतिनिधि ने छात्राओं से बंधवाई राखी

पकवा इनार। नगरपालिका क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। बोधापट्टी स्थित स्कूल में छात्र-ने छात्राओं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि राकेश जायसवाल की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। राकेश जायसवाल ने सभी को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन दिया। राखी बनाओ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। संवाद

गांव की बेटियों से चौकी प्रभारी ने बंधवाई रखी

लक्ष्मीगंज। रक्षाबंधन के मौके पर क्षेत्र के खोटही चौकी प्रभारी मनोज द्विवेदी सोमवार को खोटही गांव के खैरटीया टोला पहुंचे। उन्होंने वहां गांव की बेटियों से राखी बधवाई और उनकी सुरक्षा का बचन दिया। इस दौरान हेड कांस्टेबल श्रीराम, अंकुर, अमरजीत, सुनैना, सुनीता आदि मौजूद रहीं।

चुनावी नतीजे रोचक होंगे, बदले हुए माहौल में होगा मतदान

इस बार सितंबर और अक्तूबर में तीन चरण में होने वाले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप-प्रधान उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि ये दोनों विधानसभा चुनाव तब तकनहीं लड़ेंगे, जब तक कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 70 और 35ए वापस नहीं दिया जाता और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है।

गौरतलब है, ये दोनों पूर्व मुख्यमत्री, उमर अब्दुला अपनी बारामुला लोकसभा सीट और महबूबा मुफ्ती अपनी अनंतनाग सीट से काफी वोटों से हार गए थे।

उमर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा झटका तब लगा, जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद से वह करीब दो लाख वोटें से हार गए थे। ऐसे ही, महबूबा अपनी अनंतनाग लोकसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजर नेता, मियां अल्ताफ से हार गई। तब से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री सदमे में हैं।

बहरहाल, 5 अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर, के समीकरण बदल गए हैं। पहले पुराने राज्य में 87 सीटें होती थीं, पर इस बार 9० सीटें हैं। कश्मीर से 47 और जम्म क्षेत्र की 43 सीटें हैं। 1987 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का वकाफी दबदबा रहता था। बताते हैं, जिस पार्टी को जमात-ए-इस्लामी औरआतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन मिलता था, उसकी सरकार बनती थी। हालांकि, इस बार अलगाववाद और उग्रवाद का दबदबा खत्म हो गया है। बम और बंदूक का खौफ मिट गया है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हैं, तो चुनावी नतीजे रोचक होंगे। बदले हुए माहौल में वोट डॉले जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा की 90 सीटें के लिए चुनावों की घोषणा के बाद लोगों में एक बार फिर उम्मीद की लहर जागी है। लोग अपने इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में लोग जिस तरह वोट डालने बाहरनिकले, उसे देखते हुए उससे कहीं ज्यादा वोट विधानसभा चुनावों में डाले जाने की उम्मीद है। यह विधानसभा चुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अलगाववादी नेता इस बार या तो जेलों में बंद हैं या चुप्पी साधे बैठे हैं।

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पुराने राज्य जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ, जम्मू-कश्मीरकेंद्रशासित, तो दूसरी तरफ लद्दाख के-द्रशासित। इस बार सभी समीकरण यहां बदल गए हैं। यहां लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। जिस तरहसे लोगों ने इस बारलोकसभा चुनावों में वोट डाले और 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे ध्यान में रखना चाहिए। साल 1990 में यहां आतंकवाद शुरू हुआ था, उसके बाद के चुनावों में पांच से 15 प्रतिशत मतदान होता था, लेकिन पिछली बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 55 प्रतिशत मतदान हुआ।

पिछली बार भाजपा और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने मिलकर चार साल सरकार चलाई। साल 2014 के विधानसभा चुनावों में पीडीपी को 28 सौं मिली थीं, जबकि भाजपा को 25, पर चार साल बाद गठबंधन सरकार तब गिर गई, जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। तब से महबूबा मुफ्ती और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है।

उमर अब्दुल्ला ने घले ही एलान किया है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि वे किसी से गठबंधन करेंगे या नहीं।

लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू की दो सीटों और कश्मीर की तीन सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। महबूबा और उमर आपस में भी लड़ने वाले थे, पर बाद में दोनों हट गए थे।

इस बार के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी,भाजपा और कांग्रेस के अलावा सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉंग्रेस और अल्ताफ बुखारी के लिए चुनाव लड़ना आसान न होगा । हाल ही के लोकसभा चुनावों में पड़े वोटों को अगर देखा जाए, तो 90 सीटें में से नेशनल कॉफ्रेंस 34 सीटें पर आगे है, जबकि कांग्रेस सात सीटों पर आगे है। यहां सरकार बनाने के लिए 46 सीटें आनी चाहिए। इसी तरह, भाजपा के लोक-सभा डेय को अगर देखा जाए, तो उसको 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, पर ये सभी सीटें जम्मू में हैं।

सबसे ज्यादा जद्दोजहद महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और अल्ताफ ब्खारी की अपनी पार्टी को करनी पड़ेगी। पीडीपी को इस बार पांच विधानसभा सीटों में बढ़त मिली थी, जबकि 2014 चुनावों में उसको 28 सीटें, मिली थीं। बारामुला लोकसभा से जीते हुए सांसद इंजीनियर रशीद भी पीडीपी को कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। हालांकि, इंजीनिबर रशीद जेल में बंद हैं, पर उनके दोनों बेटे चुनावी मुद्रा में दिख रहे हैं। गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद की जम्म ऐंड कश्मीर अवामी इत्तेहाद पाटी ने उतरी कश्मीर की बारामुला लोकसभा सीट के तहत आने वाली में 14 विधानसभा सीटों में बढ़त ल्ली है, यह नेशनल कॉंफ्रेंस और पीडीपी के लिए सिरदर्द है। इन दोनों पहचान रखने वाली पार्टियों को इस बार साख बचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा।

नेशनल कॉनग्रेंस और पीडीपी सत्ता में रह चुकी हैं,कश्मीर में विकास की कमजोर रफ्तार के लिए इन दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपने पुख्ता जवाब के साथ मैदान में उतरना होगा। भाजपा और कांग्रेस को भी इन विधानसभा चुनावों में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोनों पार्टियों का वोटबैंक जम्मू की 43 सीटों पर ही केंद्रित है। पिछले दस साल में भाजपा को जम्मू में काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में शासन की वजह से जम्मू का सारा व्यापार खत्म हो गया है और बेरेजगारी बढ़ी है। कांग्रेस पारट में अंदरूनी फूट की वजह से भी पार्टी के वोटबैंक को नुकसान पहुंच रहा है।

बहरहाल, जम्मू- कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है और मुख्य चुनावी मुद्दों पर बात कहां जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुच्छेद 370, 35ए, बेरेजगारी, आतंकवाद, राज्य का द्जा दिए जाने और केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते को लेकर भी खूब बातें होंगी और देखना है कि लोग किसे ज्यादा सुनते हैं ?

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com